Foreign monopoly concerns are being allowed more facilities : tell us why. My fourth question is : will they publish a study concern-wise, industry-wise, of the outstanding banking loans and advances which are pending, and will they formulate a new banking policy as soon as possible ? Fifthly, will you provide for conversion of loans taken by private firms from public institutions—outstanding loans—to be converted into equity ? Sixthly, will you devise a new licensing policy which will really help small entrepreneurs and ban further licences to the Birla group and such other big groups ? Seventhly, will you set up an industrial and commercial intelligence system ? We have not got a modern intelligence system in the field of industry and commerce, without which it is impossible to find out what is going on. And, lastly, will you please expedite, and tell us why you are not expediting, the promised enquiry into the Birla firms, into the complaints which have been brought forward in the affairs of Birlas ?

Unless these things are done, the passing of this Bill by itself, I am afraid—though it is a little step which we welcome—is nothing. It is woefully inadequate and unsatisfactory.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : Sir, there is no dispute that inequalities have increased and there is great disparity in the different sections of society, and there has been economic concentration in a few hands. There can be no dispute also that certain strong measures are needed to meet the challenge, to see that inequalities are reduced and that disparities are reduced, and there is no economic concentration in a few hands. The question before the House is, does this Bill meet the need of the nation, that is, the need to do away with economic concentration and the need to devise ways and means by which we can do away with economic concentration in a few hands ?

Such Bills have been also enacted in capitalist societies like America. We have a Bill called Anti-trust law in America; and similarly we have an anti-monopoly law in Great Britain. Similarly, we have got a measure in Italy. But the question is, does the present Bill so far as our conditions in our country are concerned, meet the need ?

Take, for example, a few items. I will give an example, to show how a monopoly grows in our country. In our State, we were asking for two or three rice mills. We do not want any machinery from outside; it is purely an indigenous trade. We do not want any capital from outside. But the Government of India declined to allow the installation of more than one rice mill in that State. Therefore, automatically that rice mill got a monopoly in the State of Himachal Pradesh. Similarly, they have limited it to two or three rice mills in Punjab. Similarly again they have done so in every other State. The question is, how will you curb this monopoly ? This is the monopoly which grows, not because the circumstances are there which enable them to grow, but because we follow a policy which enables the growth of the monopoly. If you delicence the system, that, is if you everyone was allowed to put up a rice mill, there would have been no monopoly even in this minor industry the industry called the rice mill industry. This is how monopoly grows.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Mahajan will continue his speech on the next occasion. We now take up the motion by Shri K. N. Pandey.

15.29 Hrs.

DISCUSSION *RE.* SUGAR POLICY

MR. DEPUTY-SPEAKER : In order to guide Members in their speeches, I would like to say that the time that has been distributed is as follows : Congress (O), 12 minutes; Swatantra, eight minutes; Jan Sangh, six minutes; DMK, six minutes; CPI, six minutes; CPI(M), four minutes; SSP, four minutes; PSP, four minutes. UIPG, four minutes; BKD, two minutes; Unattached, six minutes. Congress, that is, Government, 44 minutes.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : The same matter was discussed in the Rajya Sabha for 4½ hours. It is an important subject. It is an economic issue to be discussed thoroughly. You will not be doing justice to the subject if you just give 3 or 4 minutes. The time should be extended. If necessary, we can sit late.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : There are two discussions. One is on sugar policy. The other is one the fall in prices

of sugarcane and gur resulting in losses to sugarcane growers. If you combine the two, you can have 2½ hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The suggestion will receive attention. As it is 2 hours are allotted.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : पहली बात तो यह है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है । इस वास्ते इसके लिए समय बढ़ा दिया जाए ।

दूसरी बात यह है कि आप समय का एलाटमेंट करें तो दोनों आइटम्ज को एक साथ मिला कर करें । दोनों एक ही तरह की आइटम्ज हैं । इससे समय अधिक मिल जाएगा । इस से आपको भी और सदस्यों को भी सुविधा होगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : That can be considered.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि जन संघ और सी पी आई को छः छः मिनट मिलेंगे । किस आधार पर यह समय निर्धारित किया गया है ? उनकी संख्या हम से कम है । हमारी पार्टी को भी आपने छः मिनट दिये हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is the distribution at the moment. We shall look into it.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : दो मिनट में हम क्या कह सकेंगे ।

SHRI SEZHIYAN : If the discussions are going to be separate, then the participants will have to reserve some points for the other discussion. If you combine the two, we can have some more time and all the points can be covered.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Naidu is not here. It cannot be taken up.

SHRI M. N. REDDY : He will be coming.

MR. DEPUTY-SPEAKER : When he comes, we will consider it.

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, शूगर पालिसी के सम्बन्ध में मैं एक बात हाउस के ध्यान में लाना चाहता हूं । बहुत पहले से यह एक तरह का रिवाज सा बन गया है कि जब गन्ने की सप्लाई फैक्ट्रियों को कम होती है तो गन्ने का दाम बढ़ा दिया जाता है और जब गन्ने के दाम बढ़ते हैं तो किसान अगले साल गन्ना ज्यादा बो देता है और जब गन्ना ज्यादा वह पैदा करता है तो गन्ने का दाम घटा दिया जाता है । उसका असर तुरन्त गन्ने के उत्पादक तथा उत्पादन पर पड़ता है । मैं आपको कुछ फिगर्ज देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह कैसे बात होती है । सन् 1951-52 में गन्ने का दाम 4 रुपये 69 पैसे फी क्विंटल था । उस समय 47.92 लाख एकड़ भूमि में गन्ना पैदा हुआ । 1952-53 में गन्ने के दाम कम हो गए और 3.52 फी क्विंटल कर दिये गये । गन्ने का एकड़ेज घट कर 47 लाख से 43 लाख रह गया । इसी प्रकार 1961-62 में गन्ने का भाव 4.3 फी क्विंटल था और गन्ने का एकड़ेज 59.88 लाख था । उसी प्रकार पिछले साल गन्ने का दाम दस रुपये फी क्विंटल था और इसके पहले वाले साल यानी 1967-68 में जब चीनी का उत्पादन लगभग दो तिहाई रह गया था उस समय गवर्नमेंट ने यह पालिसी अख्तयार की कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाए और पार्शल डिकंट्रोल की बात आई । पार्शल डिकंट्रोल की वजह से फी शूगर का दाम अधिक मिला और गन्ने का दाम ज्यादा हुआ । इस से गन्ने का उत्पादन बढ़ा और पिछले साल गवर्नमेंट ने यह उचित समझा कि दस रुपये फी क्विंटल गन्ने का दाम फिक्स किया जाए जब गन्ने की उपज बढ़ गई तो इस साल गन्ने का दाम 7 रुपये 37 पैसे पर है । इसका प्रभाव अगले साल उत्पादन पर पड़ेगा ।

अब तक तो यह पालिसी रही कि कभी कंट्रोल हुआ और कभी डी-कंट्रोल उसके

बाद सरकार की तरफ से पार्शल डीकंट्रोल की पालिसी अपनाई गई । उस पालसी के क्या डिफेक्ट्स और लाभ हैं, वह देश के सामने है । उस से गन्ने का दाम अवश्य मिला । लेकिन जहां कंट्रोल के समय में सारे हिन्दुस्तान में गन्ने का रेट एक ही था, वहां पार्शल डीकंट्रोल के जमाने में यू० पी० में गन्ने का दाम 12 से 17 रुपये प्रति क्विंटल, महाराष्ट्र में 10 से 15 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जब कि मद्रास में केवल 8 से 10 रुपये प्रति क्विंटल । विभिन्न सूबों में गन्ने का दाम अलग अलग रहा, एक नहीं । चीनी का बाजार सब के लिए एक सा था । जिन लोगों ने गन्ने का दाम कम दिया, उन्हें ज्यादा मुनाफा हुआ और जहां गन्ने का दाम ज्यादा था, वहां मुनाफा कम हुआ । मैं ने इस बात को उठाया कि आखिर सरकार की पार्शल डीकंट्रोल की पालिसी से किस का फायदा हुआ । क्या इस से मजदूर का फायदा होता है ? हम ने देखा है कि मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बोनस की रकम भले ही बढ़ गई है । इस से किसान को कितना फायदा हुआ है ? बावजूद इस बात के कि शूगर इंडस्ट्री गवर्नमेंट आफ इंडिया के हाथ में है, गन्ने का दाम यूनिफार्म, एकरूप नहीं रहा है ।

मैं समझता हूं कि जब गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने शूगर का कंट्रोल किया था, तो उस का उद्देश्य यह था कि किसानों के हितों की रक्षा की जाये । वह तभी हो सकता है, जब कि उस को अपने माल का उचित दाम मिले । लेकिन इस में सफलता नहीं मिली । इस में डिफ़ेक्ट यह था कि हालांकि शूगर की लेवी प्राइस 7 रुपये 37 पैसे थी, लेकिन फी शूगर इतनी महंगी थी कि गांव में किसान को चीनी उचित दाम पर मिलनी तो दूर चीनी मिलती ही नहीं थी और आज भी नहीं मिलती है ।

मैं समझता हूं कि इस बारे में जिद्द करने से कोई फायदा नहीं है । पार्शल डीकंट्रोल की पालिसी फेल हो चुकी है । सरकार कोई ऐसी मशीनरी बनाये, जो इस बात का अध्ययन करे कि कौन से उपाय किये जायें, जिन से केन प्राइस स्टेबल रहे, एक रहे, ताकि किसान को उचित दाम मिलें, मजदूर को भी लाभ हो और कनज्यूमर को भी उचित दाम पर चीनी मिल सके । मेरा सुझाव है कि किसानों के गन्ने का दाम नहीं घटाना चाहिए, बल्कि उस को दस रुपये प्रति क्विंटल निश्चित कर देना चाहिए ।

यह एक मजाक की बात है कि पार्शल डीकंट्रोल के जमाने में खंडसारी चीनी का भाव 375 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़ का भाव 175 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी की लेवी प्राइस 156 रुपये प्रति क्विंटल थी । इस में क्या औचित्य है ? चीनी उद्योग केन्द्रीय सरकार के हाथ में है । लेकिन उस के देखते हुए गुड़ का भाव 175 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी का भाव 156 रुपये प्रति क्विंटल हो गया । क्या सरकार इस तरह किसानों के साथ न्याय कर रही है ? जैसा कि मैं ने अभी कहा है, सरकार को गन्ने का दाम 10 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर देना चाहिए । चीनी पर चाहे तो कंट्रोल कर दें पर उत्पादित चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन फी कर देना चाहिए, ताकि वह सब को उपलब्ध हो, वह गांवों तक पहुंचे और शहरों में भी उचित दाम पर मिले ।

आजकल यह कहना फैशनेबल-सा हो गया है कि शूगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए । सिद्धान्ततः मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूं । लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं, उन को देखते हुए मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि क्या इस स्थिति में शूगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर के हम इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं । पब्लिक सैक्टर में इस वक्त जो बुराइयां और कमियां हैं, उन को हम देखते नहीं हैं ? हम लेबर से डील करते हैं । हम देखते हैं कि पब्लिक सैक्टर में लेबर के केसिज

कोर्ट में नहीं जाते हैं, वहां उन्हें कोई सुविधायें नहीं मिलती हैं । क्या सरकार समझती है कि इन बातों को देखते हुए भी शूगर इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करना मजदूर अच्छा समझता है ।

अनुभव यह बताता है कि किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करते समय उस उद्योग को चलाने के लिए एक प्रापर मशीनरी होनी चाहिए । इस वक्त लगभग 205 शुगर मिलें काम कर रही हैं । उन के लिए कम से कम 205 ट्रेन्ड मैनर मैनेजर चाहिए, ऐसे बोर्ड होने चाहिए, जिन में किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व हो, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें और उन के हितों की रक्षा हो सके । क्या ऐसी कोई मशीनरी सेंटर या स्टेट ने बनाई है ? नहीं । इसके बावजूद राष्ट्रीयकरण की चर्चा करना केवल एक राजनीतिक स्लोगन है, जिस में कोई तत्व नहीं है ।

बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि शूगर इंडस्ट्री को कोआपरेटिव के आधार पर चलाना चाहिए । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में लेबर कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है :

"Membership of cooperative has meant an economic and political benefit, and all this at the expense of workers and the society.

We, however, recommend that there should be a comprehensive study of the working and living conditions of labour in the cooperative sector in order to understand their position *vis-a-vis* labour in corresponding units where the nature of entrepreneurship is different. This study would provide guidance for future action."

एक प्रश्न के उत्तर में श्री शिंदे ने कहा :

"In his reply to a question raised by Mr. Madhu Limaye in the Lok Sabha some three months back relating to the profits made by sugar factories, Mr. Annasaheb P. Shinde, Union Minister of State for Food and Agriculture, stated that on the basis of information received by his Ministry from 146 out of 200 sugar factories, the net profits made by them during the accounting year 1967-68 were as follows : 116 Private sector factories Rs. 11.59 crores (net); 30 Co-operative factories Rs. 1.23 crores (net)."

इस प्रकार हर एक जायंट कम्पनी में दस लाख रुपये का मुनाफा होता है, जब कि हर एक कोआपरेटिव फैक्टरी में केवल चार लाख रुपये का मुनाफा होता है । इस से किसका लाभ हुआ ? क्या कोआपरेटिव फैक्ट्रियों ने गवर्नमेंट को इन्कम टैक्स दिया ? क्या उन्होंने कनज्यूमर्ज को सस्ते दाम पर चीनी बेची ? क्या उन के यहां लेबर के साथ बर्ताव अच्छा है ? जहां कोआपरेटिव्ज हैं, वहां उन्हें काम करने दिया जाये इस में मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन जो फैक्टरियां अच्छी तरह से चल रही हैं, उन के बारे में कोआपरेटिव या राष्ट्रीयकरण का प्रचार करना कहां तक उचित है ? इतने महत्वपूर्ण इकानोमिक सैक्टर में इस तरह के सस्पेंस का वातावरण पैदा कर दिया गया है कि मालिक सोचता है कि पता नहीं कब कोई फैक्टरी उस के मालिक के हाथ से ले ली जायेगी । इस का परिणाम यह होगा कि जो मिल-मालिक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वे भी आपना हाथ खींच लेंगे और अपनी फैक्टरियों को बर्बादी के लिए छोड़ देंगे । अगर गवर्नमेंट को वास्तव में इन फैक्टरियों को ले लेना है, तो वह ले ले । लेकिन वह डिक्लेयर तो करती है, लेकिन लेती भी नहीं है । वह कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट लेगी ।

जिला मेरठ में रामलछमक्ष शूगर मिल्ज, मुहइयुद्दीनपुर, के बारे में मैंने कई दफा श्री जगजीवन राम जी से कहा कि उस की फिनांशल पोजीशन खराब है, वह पांच महीने से बन्द है, उस को टेक ओवर कर लीजिए । वह कहते हैं कि स्टेट उस को

ले और स्टेट कहती है कि सेंटर ले । फैक्टरी तभी से बन्द है ।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : माननीय सदस्य चाहते हैं कि अच्छी फैक्टरियां मालिकों के पास रहें, तथा जो बेकार हो गई हैं उन्हें सरकार ले ले ।

श्री काशीनाथ पांडेय : मैं ने दो बातें सुझाई हैं । दस रुपया क्विंटल दाम होना चाहिए ।

These are my suggestions. The price of cane should not be less than Rs. 10 per quintal and distribution of sugar should be made free thereby creating a market for consumption inside the country. Secondly, a proper study to fix a suitable cane price should be made so that there may not be fluctuation in production of sugar every year. Then, what I say is that nationalisation is not a solution and to turn joint stock companies into cooperatives is also not a solution. Thirdly, I suggest, there should be a Corporation for sick factories in each State and the Central Food Ministry should help the States to enable them to make inefficient units efficient. My fourth suggestion is this. The Central Government has realised more than Rs. 800 crores as excise duty from the sugar factories in past 12 years. I want to suggest that they should also give some part of the realisation of the excise duty for the development of the industry and to give facilities to cultivators to become efficient units. I hope the hon. Minister will keep this in mind.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : मिस्टर नायडू का गन्ना तथा गुड़ के सम्बन्ध में डिस्कशन इस के बाद है । मिस्टर नायडू यहां मौजूद हैं । मेरा सुझाव है कि इन का जो दूसरा डिस्कशन है वह इस के साथ-साथ ले लिया जाय ।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : No, Sir. I do not want to club them. I want a separate discussion on my motion. This motion concerns only the consumers and the factory people. My motion concerns agriculturists. This motion has nothing to do with agriculturists. So, I want my motion to be taken up separately.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri K. Suryanarayana.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am the second sponsor of the motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right. I will call Shri Suryanarayana next. Now, I call Shri M. N. Reddy.

SHRI M. N. REDDY : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity. The sugar policy of the Government of India has all along been be set and characterised by *ad hoc*-ism and crisis approach which has resulted in recurring cyclical ills of either over-production or under-production and which has, again, necessitated in either giving incentives or curbing the production by imposing some cut in a particular year. There has never been a long-term policy taking into consideration the needs of the consumers in the country, and the export-need and the sugarcane cultivation that has been going on in the country. Therefore, I submit, there should be a long-range policy even at this late stage.

When we have achieved the maximum target of production during the last year, that is 35.5 lakh tonnes and we are going to have next year another 40 lakh tonnes with a carry over of more than 12 to 15 lakh tonnes, unless it is planned from now on the consumption and the utilisation of the excess production, there will again be a crisis in the sugar industry affecting the farmers. Although the sugar industry is the second biggest industry in the country, it is not like any other industry where it is concerned very much with labour. Here, it is an industry which concerns purely agriculturists. More than two crores of peasants are involved in the industry. In fact, this industry is regarded in other countries as a plantation and not as an industry. This aspect is very much overlooked when we discuss the sugar policy or the sugar industry. It is primarily concerned with the farmers and we should see how best it can benefit the farmers if there is any change in the policy which is necessary in the present context

Now, I submit, the sugarcane price that was fixed for the first time under the Sugarcane Act of 1934 was fixed in the context that this industry had been given protection in 1932. The object in giving protection was to safeguard and ensure the interests of the farmers.

15.50 Hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

Only in the interests of the growers the protection was given. But the industry has misused this protection with the result that another Act has had to be enacted, that is the Sugarcane Price Act of 1934, with a view to induce the industry to pay a particular price fixed by the Government. That is how the Central Government came into the picture in fixing the price of sugarcane for the first time in 1934 and that has continued. Because the industry has not behaved properly—it has been a very much pampered and protected industry all these years—the price has to be fixed and when the price was fixed, it was not fixed in relation to the cost of cultivation and the remuneration that they would get from the alternative commercial and other crops. Why I say this is because there have been 15 Committees appointed during the last 35 years with regard to this industry but there is only one Committee to ascertain the cost of cultivation, etc., set up many years ago and even that Committee's recommendations have not been implemented. Therefore, it is high time that a new high-level Committee is appointed to ascertain the cost of cultivation so that the price fixed under the Central enactment is more remunerative and adequate to the farmers.

The second point is that sugar production is a plantation industry. It is an agro-based industry. But we have no Board such as the Tea Board or Coffee Board or any other thing. It is high time that we have a Sugar Board in this country to regulate the price of sugarcane as well as to formulate the sugar policy for the whole country taking into account the long-range needs of the country. I would request the Minister to constitute a Sugar Board analogus to the Tea and Coffee Boards so that it can do full justice. The present Sugar Directorate is not in a position to do justice. They are very much afraid. They are very much panicky in sugar matters because they think that the policy that is being evolved from time to time is not evolved on considerations of national interest but on the influence of one section or the other. They are leaving the matters to the Chief Ministers for decision who are in no way better than the Sugar Directorate. It is mentioned in the Sugarcane Control Order 1966 that before fixing the price the organizations of sugarcane growers in various States will be consulted but that is never done. I assert that the Government completely ignored and overlooked the peasants in the matter of fixation of prices and they have violated the statutory provision under the Sugarcane Control Order 1966. It is high time that the peasants are taken into confidence and consulted before the price is fixed.

Now, about more than Rs. 100 crores is levied as excise duty and the cost of sugar production in this country is many times the cost of sugar production in other countries. What is the solution for it? When we have surplus production and we are supposed to export more than 3 lakhs tonnes every year, we have exported only 90,000 tonnes. So the solution is reduction in the cost of production. That can be done only by improving the yield per acre of sugarcane and also the sucrose content, but nothing has been done towards the development of sugarcane production as well as improvement of the sucrose content by the State Governments. They only collect the purchase tax all over the country and they do not spend this amount at all. Only 30 to 40 per cent is spent on the cane development and infrastructure facilities and the rest is treated as general revenues. Therefore, the Central Government should come into the picture and enact a central legislation or bring pressure on the State Governments to utilise the entire amount on sugarcane development which will reduce the cost of sugarcane cultivation and also reduce the cost of production of sugar.

Regarding the utilisation of by-products, we have to consider the two by-products. One is bagasse and the other is molasses. We have been reading in the papers that there is going to be a paper famine during the next five years. Bagasse is the best raw material which can be used for the

[Shri M. N. Reddy]

manufacture of paper. Therefore, this should be taken into consideration which would also help the sugar industry in reducing the cost of sugar production by utilising the bagasse for a better purpose like paper manufacture.

The second by-product is molasses. We have had control on malasses, distribution, storage, price etc. since 1941. During the British times the then British Government imposed control during the 2nd World War for an emergency purpose. But unfortunately that continued from 1941 to this day. What is the rate of the molasses ? It is merely Rs. 7 per ton which does not even meet the storage cost. The same per ton cost in the black market or open market is Rs. 700 per ton; and it is 100 times more. It is high time this control is removed on molasses so that they can sell away these molasses in the open market and reduce the cost of production of sugar and they can distribute sugar to the consumers at a cheaper rate.

About partial decontrol, during the last 2 years it has partially benefited the sugarcane growers but it has fully benefited the factory owners. They should not have any grievance about this. It is high time that this policy is revised and decontrol is effected.

As regards nationalisation so much is being said these days. More than 2 crores of farmers are engaged in the sugarcane industry and more than 140 private industries are there who are not behaving properly, who are not effecting any modernisation or rehabilitation and paying proper prices to the farmers as recommended by the Gundu Rao Committee. It is high time Government takes over these factories, not manage themselves through bureaucracy, but hand them over to the sugarcane growers constituting their cooperatives. As regards compensation to the private factories, the nationalised banks can give loans to these cooperatives and pay off the compensation to the extent of Rs. 100 or Rs. 150 crores over a period of 3 or 4 years. Later on the entire capital can be recovered from the prices of cane supplied to the factories in instalments over a period of 3 to 5 years. Thereby the farmers themselves can manage the factories with more efficiency. There will be a direct involvement and participation of grower in the management of the factories.

I appeal to Shri Jagjiwan Ram that be may, as a parting gesture to the farmers of this country, especially the sugarcane growers, constitute a Sugar Board and fix the minimum and floor price of sugarcane at Rs. 10 per quintal, that is, Rs. 100 per ton, which would solve the problem of the farmers.

*SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru) : Mr. Chairman, Sir, I hope the hon. Members who spoke before me are interested in helping the farmers in getting better price and not in embarrassing the Government. The Government say that whatever legislation is brought up by them, it is only to help the farmers. But farmers hold a different view. During their tours the Ministers are apprised of the difficulties of the farmers. But it is sad to note that no action to remedy the situation is taken by the Ministers. The sugar industry has a bright future. During the last ten years the farmers have invested a lot of money on sugarcane farming and when the profits are being ploughed back, the vacillating policy of control and decontrol has demoralised them.

16.00 Hrs.

We have Coffee Board, Tea Board etc. There were so many boards during the British time also. But for such a profitable industry it is unfortunate that there has not been any board to regulate and direct its policies. In this, I whole-heartedly agree with Mr. Narayan Reddy for the constitution of a Sugar Board to manage this industry on better and more profitable lines. As Mr. Pandey has stated some sugar factories in cooperative sector are doing well and some are not. Where the sugar factories in the private sector are not functioning on sound lines, the Government should come forward and encouraged small farmers to set up cooperatives in their place. Ten years ago the Anakapalli factory was on the verge of closure when the small farmers formed a cooperative society and took over the factory after

*The original speech was delivered in Telugu.

paying Rs. 20 lakhs. The factory functioned well thereafter, paid good dividends and is now worth Rs. two crores. The main difficulty is they have to deal with the State Government as well as the Central Government like the prorertial wife dealing with two husbands. The responsibility is divided between State Government who give the licences and the Central Government who fix the price. Whether the factories are running properly or not, the State Government do not take any interest. When we ask the Central Government to intervene they are cool to the proposal. If they want to benefit the farmers, both the State and the Central Government in consultation with each other, should formulate policies towards this end. If the sugar industry is in the cooperative sector, the conditions would improve. For this purpose, it is essential that a statute for forming cooperatives in each State should be enacted. Among all the States, Maharashtra tops the list in the matter of cooperative sugar industry. Why is not similar progress being made in other States? This is mainly due to the weakness of the State Government and their defective and oft-changing policies. There is nothing wrong with the farmers or with the functioning of the factories. The main drawback is the malfunctioning of cooperatives in the State. Even though the State Government has power to curb these mal-practices, it is their reluctance to take firm action which results in these factories not being successful in the cooperative sector. This fault therefore lies squarely at the door of the State Government. Some people suggest that the sugar industry be taken away from the private sector and entrusted to the cooperative societies. The sugar industrialists in U.P. and Bihar are today thinking of winding up the factories. In Anakapalli when Mr. Ramana M.P. took over the management of the factory about ten years ago, he had to face difficulties and it was a problem for him to make it a going concern. He was therefore forced by circumstances to leave. This sugar industry is now passing through a series of crises. When other countries who are less developed and economically backward than ours are able to produce more not only sugar but other agricultural products as well, it is tragic that we are sitting in this august House and passing pious resolutions. The Land Reforms policy of the Government is also very discouraging in that the farmers are not coming forward for investment in growing sugarcane. Because of the vacillating policies of the Government, the people are losing faith in the Government. I therefore request that the suggestions made by Shri Naryana Reddy and Shri Kashi Nath Pandey from their personal experience should be favourably considered by the Minister who also belongs to the farmers class. This will go a long way in infusing confidence in the farmers and the sugar industry will have a great future. Not only Centre meet the domestic demand of sugar but also export sugar. When the sugar industry is on a sound footing and the farmers and the industry got a remunerative price, they can do away with the subsidies all together.

My submission is therefore that the Government should constitute the Sugar Board immediately. Unlike the Agricultural Commission headed by an I.C.S. officer, and without treating this as merely an assignment for computers, the Board should consist of Members who are drawn from the farmer's class and who have personal knowledge and experience of the industry. With this I conclude my speech.

SHRI N. K. SOMANI (Nagpur) : The virus of nationalisation and controls has overtaken our decision-makers to such an extent that we now either completely disregard the realities of the situation or we do not look into the problems where an industry is critically situated or do not examine dispassionately the various factors that are associated. One can understand this that the Government can find a valid excuse to nationalise one sector of industry or another. There has been a curious peculiarity developed of late—I do not know whether you should call it diabolic intelligence—and this Government has gone to the extent of saying that the State Government can nationalise an industry situated within the State. I would like certainly to accept this and to challenge and warn the Government that if this trend continues, we will have to persuade the Orissa Government also to take over the Central Government undertakings which are situated there, because if the Law Ministry's opinion holds good in one

[Shri N. K. Somani]

particular case, that you can take over an industry situated in U.P. and nationalise it and go ahead irrespective of all considerations, I think the same rule will also hold good in interpreting that the Central Government undertakings situated in any other State can also be taken over by that State, and that rule can be complied with as far as denationalisation is concerned or State take-over is concerned. I would then like to know what would be the final reaction of the Law Ministry.

SHRI S. M. BANERJEE : You mean nationalisation of the Orissa Government ?

SHRI N. K. SOMANI : We will do what is to be done, it is already a national Government.

SHRI RANJIT SINGH (Khalilabad) : Because the West Bengal Government is not nationalised, he thinks others also are not.

SHRI N. K. SOMANI : I can understand it if there are urgent economic demands and if they can find a valid excuse, but here I am constrained to say that the content of sucrose and sweetness that is existing in a sweet commodity does not justify the bitter malcontents and functioning that we have been witnessing so far.

I would like to give a very brief quotation from Mr. Nehru who is supposed to be the dayen and father of socialism in this country, where in clear and unmistakable terms be said in 1956—I hope his daughter would remember his words and also some of the new fashioned advocates of socialism and controls that have been produced lately :

> "We talk about the private sector and the public sector and some people seem to think that the easiest way to advance would be to put an end to the private sector entirely and call everything public sector."

He added :

> "I think that this would be a most impractical and unprofitable approach and we shall say that this is a stupid and infantile approach."

These are not my words. I am quoting exactly from the late Prime Minister Nehru. I also want to emphasise that these are not statements which were true then and which have now become untrue, these are going to be true for all time to come because we swear by our Constitution which accepts a mixed economy, and therefore, the merits of any particular question will have to be gone into before political snipes are taken when C. B. Gupta is associated with it, or another stand is taken when West Bengal is associated with it.

I will go into the background very briefly. Since 1967-68 and 1968-69 sugar production has gone up considerably and I am prepared to pay a compliment to Babuji in this matter. He started with a structure of 60-40 relationship between controlled and free market sugar, it went up to 70-30, but the result has proved that this is no more a case of a hypothetical situation which demands any sweeping take-overs like this. If at that particular critical moment a certain amount of flexibility, initiative and incentive had not been provided not only to the sugarcane grower but also to the industry itself, we would certainly not have had the surplus production of sugar that we are seeing today.

I would also like to say that although it is not directly related, the problem of *gur* and *khandsari* will also have to be solved for all time to come since we have to have a total equilibrium. I think the latter motion would seek to go into it. I call them the favoured children of the sugar industry or the Sugar Minister. But, for lack of time, I would not like to go into that, except to say that we will have to take a long-term view whether it is procurement or cultivation of sugarcane, employment, marketing, ownership or distribution. And as far as the compartmentalisation of sugar, *khandsari* and *gur* are concerned, let the people of India know what exactly is desired of them or is expected of them. Then only, the fourth Plan revised target for the sugar industry, of 48½ lakh tonnes now provided, can be fulfilled.

I would like to add this : that we would like to have a raising level for the people of this country, and just as we expect them to turn over from coarse foodgrains to finer foodgrains, just as we expect them to take over from coarse textiles to fine and superfine textiles, there has to be a positive policy of this Government to

induce them to change over in their personal consumption from *khandsari* and *gur* to refined sugar. After all, it is only very reasonable to expect, and therefore, beyond the level where *gur* and *khandsari* are absolutely necessary, this integrated approach will have to be done in such a manner that in times to come sugar becomes easily available to the poor people of this country.

There is one point which is very important. It is about our sugar quota for exports. I know it for a fact and the hon. Minister knows that the 3½ lakh tonnes quota that has been given to India by the International Sugar Association cannot be fulfilled as long as the present high prices compared to the world prices prevail in this country. There are several European countries who are willing to buy over your sugar quota and this is a chance where, without losing your future rights, —because if you for one or two or three years do not export according to your quota, do not make any attempt or make negotiations on this basis, you are likely to lose this right for all times to come —you can hold the field. Therefore, I would urge that the Government ought to examine this point of view also.

There is a Development Council for the sugar industry as there is a Development Council for all the industries. But I regret to say that the entire functioning of this Development Council has been reduced to a farce. They go into the entire aspect of the industry in which the DGTD and your Ministry are associated. There is a clear indication that additional capacity that is required for the fourth Five Year Plan, according to the Development Council's decision should be handed over to the existing units so that those of the units which are either sick or uneconomical or are marginal units can come back to normal operation and then only the Government could think of creating an additional capacity, but the Government will not do anything about the sick sector. I am to saying that the Government should squander public money out of the exchequer and take over the sick mills. I know that, as it happened in the case of the textile industry, they would not be able to run it, but conditions will have to be created by either allowing the sick mills to be shifted to another place which was the thinking once upon a time or we will have to do something by which our industrial units can manage an overall productive policy and pattern in the interests of the consumer and in the interests of the overall development of the industry. I hope such decisions would be taken which will not hamper the growth of this industry at all.

श्रीमती सावित्री श्याम (आंवला) : सभापति महोदय, श्री काशीनाथ पाण्डेय जब चीनी उद्योग के सम्बन्ध में बोल रहे थे तो मैंने उनका भाषण बड़े ध्यान से सुना लेकिन उनका भाषण सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे अफसोस हुआ उनकी प्रगतिशीलता के ऊपर, उन के समाजवाद के ऊपर और एक लेबर लीडर होने के नाते उनके नेतृत्व के ऊपर जिसके कारण वे आज देश के लेबर लीडर कहलाते हैं। मैं इस देश के मजदूरों और आई० एन० टी० यू० सी० के वर्कर्स को आवाहन करना चाहती हूं कि वे आंख खोल कर देखें कि कहीं उनके नेतृत्व के कारण उन लोगों के हितों को नुकसान न पहुंचे।

चीनी उद्योग भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा उद्योग है। इस देश में उसकी दूसरी पोजीशन है। जहां तक उत्तर प्रदेश और बिहार का सम्बन्ध है, इन दोनों प्रदेशों में यह उद्योग एक की इन्डस्ट्री है। वहां की अर्थ-व्यवस्था इस चीनी उद्योग पर ही अवलंबित है। उत्तर प्रदेश के 85 हजार वर्कर्स, इंजीनियर से लेकर सीजनल वर्कर तक, इस उद्योग के अन्दर लगे हुए हैं।

इस उद्योग को 1930 में प्रोत्साहन दिया गया, आज नहीं जबकि ब्रिटिश राज्य था। सन् 1930 में जब बाहर चीनी भेजनी थी तब यह प्रोत्साहन दिया गया और इसलिए भी दिया गया कि गन्ने के उत्पादन को और मजदूरों को प्रोत्साहन मिले, उनके हितों की रक्षा हो। लेकिन

[श्रीमती सावित्री श्याम]

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों गन्ने के उत्पादन और मजदूरों के हितों की रक्षा का ध्यान कम किया जाने लगा, उनके हितों को रक्षा नहीं हो सकी ।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि अब यू० पी० में 1937-38 में इंटेरिम गवर्नमेंट बनी दो साल के लिए तब उसने एक शूगर फैक्ट्री एक्ट बनाया और उसमें यह कहा गया कि हम शूगर मिलों को अपने हिसाब से रेग्युलेट करेंगे, गन्ने की कीमतें हम निर्धारित करेंगे, मजदूरों के हितों की रक्षा हम करेंगे, उनकी मजदूरी हम निर्धारित करेंगे, चीनी मिलें कितना गन्ना लें और कितना गन्ना गुड़ और शुगर के वास्ते दिया जाए, यह सब हम निर्धारित करेंगे ।

लेकिन सन् 1951 का जब सेंटर का एक्ट बना जिस को इंडस्ट्रीज कंट्रोल रेग्युलेशन एक्ट कहा जाता है तब उत्तर प्रदेश से इस अधिकार को ले लिया गया और यहां से गन्ने की कीमतें निर्धारित होने लगीं और लाइसेंस मिलने लगे ।

आप, आज जो स्थिति है, उसको देखें । 1936 में जो फैक्ट्री उत्तर प्रदेश और बिहार में लगी थी आज उसकी हालत को आप देखें । जो इंडस्ट्री दस लाख में लगी थी आज उसकी कीमत जीरो हो गई है, उनकी कोई क्रशिंग पावर ही नहीं है । उनकी मशीनरी को मार्डनाइज नहीं किया गया है, पिछले वर्ष जब बजट प्रस्ताव यहां उपस्थित हुए थे तो उन में मार्डनाइजेशन रिबेट की बात कही गई थी, डिवेलेपमेंट रिबेट की बात कही गई थी, उन को लोन देने की बात कही गई थी, शूगर सैस में उनको छूट दी गई थी तथा दो परसेंट छोटी-मोटी चीजों को ठीक-ठाक करने के लिए रिबेट भी उनको दिया गया था लेकिन इस सब का नतीजा क्या हुआ ? मशीनें ठीक करने के बजाय मिल मालिकों ने एक्सटेंशन किया । अगर किसी मिल की क्रशिंग कैपेसिटी पचास हजार टन की थी तो उसको उन्होंने एक लाख कर दिया । बजाय इसके कि मशीनों को ठीक किया जाता, उनका डिवेलेपमेंट किया जाता, शूगर पैदा करने की कैपेसिटी को बढ़ा लिया गया । इससे न मजदूरों को, न केन ग्रोअर्ज को और न चीनी खाने वालों को लाभ हुआ । उपभोक्ताओं को चीनी ठीक कीमत पर नहीं मिल सकी ।

आज उत्तर प्रदेश में एक एजीटेशन है कि सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करे । 120 एम एल एज ने जोकि दोनों ग्रुप्स के हैं, उन्होंने इसकी मांग की है । जब हम में कोई लड़ाई नहीं थी तब इस प्रकार का वहां एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले । 5 अक्तूबर, 1969 को इस के बारे में कैबिनेट का फैसला हुआ था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाए । प्रदेश कांग्रेस की एग्जैक्टिव ने भी यह तय किया था कि इनको ले लिया जाए । लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है । आजकल उत्तर प्रदेश और केन्द्र के बीच में इसको ले कर लड़ाई हो रही है । उत्तर प्रदेश की ला मिनिस्ट्री यह सलाह देती है गुप्त जी को कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगर सारे देश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होता है तब ही कर सकती है जबकि यहां की ला मिनिस्ट्री यह राय देती है कि उत्तर प्रदेश को पूरा अधिकार है राष्ट्रीयकरण करने का । मैं नहीं समझती हूं कि इन दोनों की लड़ाई में गन्ने के उत्पादकों, कन्ज्यूमर्स और मजदूरों को क्यों नुकसान पहुंचे । मैं बाबू जगजीवन राम जी से प्रार्थना करती हूं कि जो आपका रैग्युलेशन एक्ट 1951 का है, उस में आप संशोधन करें और जहां आपने यह कहा कि गन्ने की कीमत आप निर्धारित करेंगे, उसको खत्म करके आप यह कहें कि प्रदेश सरकारें करेंगी । आप शूगर इंडस्ट्री के लिए एक आटोनोमस

कारपोरेशन बनायें और शूगर इंडस्ट्री को उसके अन्तर्गत लायें । तभी किसानों का, मजदूरों का और उपभोक्ताओं का भला हो सकता है ।

मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है । मैं उनके दुख दर्द को समझती हूं । प्रधान मंत्री मेरे निर्वाचित क्षेत्र में गई थीं । तब रुहेलखण्ड का एक डैलीगेशन उन से मिला था और उसने मांग की थी कि मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले । मैं मांग करती हूं कि शूगर इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हो । अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एजीटेशन करेंगे हम इसके लिए सत्याग्रह करेंगे । चाहे जो भी सरकार हो, उसको इसका सामना करना पड़ेगा । राष्ट्रीयकरण समय की मांग है । 1951 का जो एक्ट है उसको आप रिपील करें । तब जो रोड़े उत्तर प्रदेश की सरकार के रास्ते में हैं वे दूर हो सकेंगे । आप अपनी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर डालें और वह आप पर डाले, इससे काम नहीं चल सकेगा । केन ग्रोअर, मजदूर, खाने वाले सब के हितों को आपने चोट पहुंचा रखी है । यह बात बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है ।

श्री शारदा नन्द (सीतापुर) : मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है । जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, इस विषय को यहां बहुत पहले आना चाहिये था । लेकिन इसको टाला जाता रहा है और आज जा कर इस पर बहस की जा रही है । शूगर की एक बहुत ही विषम समस्या है । सारे देश के सामने यह समस्या है कि शूगर इंडस्ट्री का क्या किया जाए । शूगर इंडस्ट्री एक बीमार बच्चे की तरह से है । अब सवाल पैदा होता है कि इस बीमार बच्चे को किस की गोद में दिया जाए ? या तो इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए या सहकारी आधार पर इसको चलाया जाए या कोई और रास्ता निकाला जाए । जब राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो एक सवाल यह भी पैदा होता है कि ऐसा अगर किया जाता है तो पैसा कहां से आएगा । साथ ही यह बात भी सामने आती है कि इससे सरकार को घाटा होगा । जो पैसा सरकार लगायेगी वह किस प्रकार से और कहां से लाएगी । ये सब समस्यायें हैं जिन पर विचार होना अनिवार्य है ।

जिस प्रदेश से मैं आता हूं वह प्रदेश चीनी का सब से बड़ा उत्पादक प्रदेश है । आज वहां 71 के करीब मिले चल रहीं हैं । अधिकांश मिलें प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं । कुछ कोआपरेटिवज़ के द्वारा भी चलाई जा रही हैं । आज उनकी हालत क्या है ? अधिकांश मिलें लड़खड़ा रही हैं । किसी की आर्थिक दशा खराब है, किसी की मशीनरी खराब है, किसी का कुछ और खराब है जो राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं, उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर गरोल शूगर फैक्ट्री को सरकार ने करीब एक साल पहले अपने हाथ में लिया था ; लेकिन आज तक वह चली नहीं है । वहां पर किसानों का और मजदूरों का पैसा बकाया है । सरकार ने किसानों और मजदूरों का बकाया पैसा आज तक भी अदा नहीं किया है । आगे क्या होगा, पता नहीं । किस प्रकार से इसको चलायेंगे, इसका कुछ पता नहीं है ।

सबसे बड़ी समस्या किसानों में व्याप्त अनिश्चितता की है । यह अनिश्चितता इसलिये पैदा हो रही है कि उनको प्रोत्साहक मूल्य नहीं मिलता है । जब गन्ने की पैदावार कम होती है तो चीनी मिलें चिल्लाती हैं कि उनको गन्ना चाहिये । तब सरकार बैठ कर सोचती है कि क्या किया जाए और सोचने के बाद गन्ने की कीमतें बढ़ाती हैं । लेकिन किसान को पहले से उचित कीमत और प्रोत्साहक मूल्य नहीं देती और न ही इसके बारे में कोई निर्णय लेती है ।

[श्री शारदा नन्द]

मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । सरकार द्वारा जो फार्म चलाये जा रहे हैं उनमें खर्चे के हिसाब को आप देखें । उनमें खर्चा 3826.35 रुपये पर हैक्टर आता है और यह तब आता है जबकि उनके लिए सिंचाई की दर साठ रुपए दर हैक्टर निर्धारित है । इस पर पर आम किसान को पानी मुहैया नहीं होता है । अधिक दर पर उसको पानी मिलता है । अगर गन्ने की कीमत इसी प्रकार से किसान को मिलती रही तो किसान मारा जाएगा । किसान का गला, आप न घोंटें ।

बहुत सी मिलों के ऊपर किसान का पैसा बकाया है । सालों हो गए हैं । किसानों को वह पैसा नहीं मिला है । कितना पैसा बकाया है इसका जवाब सरकार ने दिया था । उसने बताया था कि 2995.82 लाख रुपया किसानों का बाकी है । अभी तक किसान सोच रहा था कि उसका पैसा उसको क्यों नहीं मिल रहा है ।**

मैं साफ कहना चाहता हूं कि किसान की समझ में अब आया है कि उसका बकाया पैसा उसको क्यों नहीं मिल रहा है । क्यों मिल मालिक उसको उसका बकाया पैसा अदा नहीं कर रहे हैं.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जरा बैठ जायें । यह बात इस हाउस की डिगनिटी के खिलाफ है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री शारदा नन्द : यह सर्वविदित बात है ।

SHRI RANJEET SINGH : He has made a statement of fact.

सभापति महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जायेगा ।

श्री शारदा नन्द : आज किसान को समझ में आया है कि मिल मालिक क्यों उस का पैसा दाब कर बैठा है और सरकार उसको क्यों नहीं दिलाती है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने जिस भाषा का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, वह बहुत आपत्तिजनक है और वह रिकार्ड पर जाने लायक नहीं है ।

श्री शारदा नन्द : आज किसान की हालत को देखने वाला कोई नहीं है । वह परेशान है और कोई उसकी परेशानी को दूर करने वाला नहीं है । किसानों का जो पैसा मिल-मालिकों पर बकाया है, सरकार उसको नहीं दिलाती है ।

इस समस्या को हल करने के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं । हमारे खाद्य मंत्री महोदय कभी कभी कहते हैं कि मद्रास और मैसूर में शूगर मिलें अच्छी तरह चल रही हैं । यह अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? वहां को-आपरेटिव्ज द्वारा चलाई जा रही मिलों को घाटा हो रहा है, जब कि कुछ मिलें ठीक तरह से चल रही हैं । मैं आप के माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों को चीनी मिलों का मालिक बनाया जाये । इसके लिए स्वायत्त निगम बनाया जाये, जिसमें किसानों, मजदूरों और कनज्यूमर्स का प्रतिनिधित्व, हो, जिस में विधान सभाओं में किसानों के नुमायंदे हों । अगर एक स्वायत्त निगम की स्थापना कर के इस उद्योग को चलाया जाये, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश मिलों की आर्थिक दशा बहुत खराब है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिल कर सोचें कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है । इस बारे में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए । बहुत सी मिलें

**Expunged as ordered by the Chair.

ऐसी हैं जो सही हालत में चल रही हैं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि उन को डिसटर्ब किया जाये। जो बहुत सी मिलें खराब हालत में हैं, उन के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Mr. Chairman, Sir I am glad that we have got an opportunity to discuss this issue. The sugar industry has been suffering due to so many ills for the past few years. Unfortunately, as hon. Members before me have pointed out, the Government did not have a long-term clear policy in regard to sugar. The first bungling, I should say, started when the Government of India, during the time Shri Jain was the Food Minister at the Centre, declared UP and Bihar as the sugarcane belt of this country and started issuing a lot of licences. I hope I will not be mistaken when I say that unfortunately people failed to appreciate at that point of time that sugarcane is a tropical crop and the climatic conditions south of the Vindhyas are more conducive for a better output of sugarcane than the biting cold that is prevalent for about three months in the northern belt due to which the yield per acre in the Gangetic Plain is still suffering in spite of the Kanpur institute which is doing its best. With the best efforts of the Kanpur institute the per acre yield in the Gangetic Plain, Punjab and some other places in the north could not reach more than 30 to 35 tonnes per acre whereas in the South, in my State, the per acre yield is up to 60 to 70 tonnes in some areas and the average is 45 to 50 tonnes with the difference that the sucrose content did not rise so much as it has risen in this belt.

Here I would like to appeal to the Minister that it is high time that we should have an institute of the type existing in Kanpur to cater to the needs of farmers in the south. I think, Government should consider this because that will raise the output of sugar tremendously in the southern belt of our country.

Now that the factories have come into being in the northern belt, I would like to plead with the Government that at least in future, there should be a crop pattern in the country. For example, in Tamil Nadu, we do not have enough pulses. We do not have wheat. Now that we have taken to wheat and we have learnt to take enough wheat, if the Government at some future date were to tell us that they will not be having enough wheat to spare to us, probably, we will be hard put. Then, we will have to divert some of our precious land which is more suited for other crops to wheat. Such kind of things are not desirable.

Now, for instance, in regard to pulses, the Tamil Nadu Government has got a plan to increase the acreage under pulses. I think, if you look at it scientifically, it is not proper for us to do that because pulses will not grow so good as they are grown in Madhya Pradesh or in Punjab. But since we are in need of pulses and, in case we do not get them from Madhya Pradesh and Punjab, we have to go in for that.

Here, my point is that it is the responsibility of the Central Government to plan that. Our country is of a continental type. There are certain areas which are best suited for certain crops. You should bear that in mind. When you allocate areas for cotton, when you allocate areas for sugarcane, for wheat and other crops, there will not be any national waste which is going on in various crops in various States. Now, every State seems to think that they have to meet their entire demands for pulses, for sugar, for paddy, for everything. This is a very dangerous trend. It is impossible also to do that. It is not good and conducive to the betterment of the economy of the country. The Central Government should bear that in mind.

With regard to sugarcane price, there lies the difference. Of course, it is true, in my part of the country, the farmers raise a hue and cry that the minimum price that is given to their brothers in the north is much better than the price that is given to them in the south. But if you take the overall position, our position is not so bad. Though we get about Rs. 70 or Rs. 73 per tonne, that is the minimum fixed by the Central Government, as against Rs. 100 in other places where the tonnage is much less. Then, naturally, the per-acre income that we get

[Shri S. Kandappan]

is in no way less than the per-acre income that our brothers in the north get.

The point that I want to make here is as to what you are going to do to regulate the cost price of sugar and also to see that the consumers do not suffer and in case, as we can very well envisage in the near future, there is going to be a glut in the market, what is going to be the adverse effect which is likely to be there on the factories as well as on the sugarcane growers. The Government do not have any clear-cut policy with regard to this. With regard to the Fourth Plan target, I do not know whether they are going to create any additional capacity or they are going to give permission to the already existing mills to increase the capacity.

I would like to put the case of my State to the hon. Minister on this occasion. For the past two years, the Tamil Nadu Government has been suffering and the mills the factories, that are there either in the private or in the cooperative sector, are not able to cope up with the demand of the farmers. The sugarcane area is so much increased that our crops are standing in the field for 13 to 15 months. As per the climatic conditions there, the average period is 10 to 11 months. The eleventh month is considered to be the best month for cutting the crop. I have got about 4 to 5 acres of land under sugarcane and my crop has been standing in the field for 13 months or so and I am told that the sucrose content will be much less and the factories will suffer and the farmers will also suffer. So, the factories are not able to cope up with the area that is already sown under sugarcane. There is a genuine case. At least about the co-operative sector, about which so many proposals have been forwarded to the Central Government from our State Government, the Central Government should consider the case sympathetically and, we desperately need at least a few more factories in the cooperative sector. In this connection, I would also like to point out that the Centre's attitude is not so good. In Salem district, there is one cooperative factory in which all the farmers are members and I am glad to announce here that the entire capital outlay of that factory has been paid back by the income they were able to derive from that factory alone. This year, they have earned a net profit of Rs. 30 lakhs or so in that factory. It is running at a good profit. Now, the area has increased. We wanted to increase the crushing capacity for which we applied for an import licence to import the machinery to erect additional capacity in the factory. It is about more than a year. We have been only waiting for the licence.

MR. CHAIRMAN : Why do you want to import ?

It can be manufactured in the country.

SHRI S. KANDAPPAN : I am giving the case. I know it can be manufactured in the country. We invited quotations from various manufacturing sources in this country. They said that it would take 2 years. But we wanted to do the crushing right now. Crops are standing in the field. After all what is the foreign exchange involved ? A few lakhs only. You are spending lakhs and lakhs of rupees for the import of lipstick and other luxury articles. Can't you give in the interests of the farmer a few lakhs and that also, not for a private factory, but for a co-operative factory ? It is for the Government to see that the farmers' interests are protected. If the Government is confident that they can protect the interests of the farmers by nationalisation in Uttar Pradesh and other areas, well they can go ahead. But, as far as my State is concerned, in the co-operative field we have channelised the entire credit facility to the farmer and the entire investment to the farmer through the co-operatives. There is being created a nucleus around every factory which is conducive to the functioning of the factory. Some such kind of procedure should be followed in other States also and I would plead with the Minister that in future fresh licensing should be only in those areas where it is more conducive for the growth of sugar cane and not in other areas which are more conducive to grow wheat.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं नायडू साहब और रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन की तरफ से यह रिजोल्यूशन आए हैं और मंत्री महोदय का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि

उन्होंने इस के लिए गवर्नमेंट का टाइम निकाला है । असल में शुगर की प्राइस से मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है । मैं तो ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं शुगर केन की प्राइस से । साफ बात है कि मुझे शुगर से क्या दिलचस्पी हो सकती है जब कि किसानों को शुगर मिलती नहीं है, शुगर को जो पैदा करने वाले हैं, जिन के खेत में शुगर केन पैदा होती है, उन को जब शुगर मिलती ही नहीं है तो मुझे उस से कोई हमदर्दी नहीं है । तो चूंकि अगले आधे घंटे में हम उस के लिए क्या कह सकेंगे इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि इसको और उस को दोनों को शामिल कर के उस पर मैं बोल लूं ।

मैं मोटी मोटी बात कहूंगा कि वक्त बदल गया है । आज पता नहीं हर आदमी क्या समझता है कि पता नहीं किसान क्या खा रहा है, किसान कितना कमा रहा है । सभापति महोदय, आप खुद किसान हैं, आप जानते हैं ।

कुछ भाइयों की तरफ से कुछ ऊटपटांग बातें कही गईं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बाबू जगजीवन राम जी के सिलसिले में वह अपने को ज्यादा किसान समझते हैं । लेकिन खैर, मैं वह बात छोड़ता हूं । सब से पहली बात जो हमें महसूस करनी है वह यह है कि गन्ना किसान का खून खा लेता है ।

अब्बल तो कास्ट आफ प्रोडक्शन हर एक जिन्स पर ज्यादा होती है लेकिन खास कर के गन्ना पैदा करने के लिए जितनी कास्ट आती है, सीड है, वाटरिंग रेट है, बिजली का है, निराई है, बंधाई है, कटाई है, कोल्हू का देख लीजिए और फिर मंडी तक पहुंचते पहुंचते जितना लेबर उस में आता है और जितनी इन्वेस्टमेंट उस में आती है, उतनी और किसी चीज में नहीं आती । उस का इन्वेस्टमेंट सीड पर या पानी के दाम जो बढ़ गए हैं उन पर इन सब को मिला कर शुगर केन पैदा करने में इतना ज्यादा हो जाता है कि जो और किसी क्राप पर नहीं होता है । तो मैं जो एक यह कहना चाहता हूं कि यह जो कीमत आप मुकर्रर करते हैं, बड़ी मेहरबानी कर के आप दस रुपया क्विंटल मुकर्रर करते हैं, मैं कहता हूं कि वह दस रुपया भी कम है लेकिन वह उसको भी नहीं मानते हैं । दस रुपया क्विंटल भी माना नहीं जाता । अब्बल तो दस रुपया बहुत कम है । लकड़ी बीस रुपये क्विंटल और वह भी एक बेकार सी लकड़ी और गन्ना जो एक साल की मेहनत के बाद पैदा होता है, बेहतरीन जमीन में, सारा कुनबा मिल कर लगता है, सब से ज्यादा मेहनत जिसमें करनी पड़ती है, सब से ज्यादा पैसा जिस के प्रोडक्शन पर खर्च होता है, एक साल में एक फसल जाकर होती है । वह दस रुपये क्विंटल । लकड़ी बीस रुपये क्विंटल, सूखी लकड़ी और गन्ना दस रुपये क्विंटल . . . . (व्यवधान) . . . सभापति महोदय, मुझे कह लेने दीजिये । मुझे ज्यादा नहीं कहना है । एक बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कम-से-कम दस रुपए क्विंटल जो आपने किया है उसे मेहरबानी करके साढ़े बारह या पन्द्रह रुपये तक करें ।

सभापति महोदय : दस नहीं है, सात है ।

श्री रणधीर सिंह : मैं कहता हूं कि पिछले साल दस किया था । आप भी थे उस कमेटी में, मैं भी था, बाबू जी चेयरमैन थे । दस रुपये क्विंटल की कीमत मुकर्रर हुई थी ।

सभापति महोदय : लेकिन किसी ने वह कीमत नहीं मानी ।

श्री रणधीर सिंह : वही मैं कहता हूं कि साढ़े सात में लिया या और उस से कम में लिया । आप की बात कोई नहीं मानता ।

[श्री रणधीर सिंह]

बाबू जी की बात एक मुझे ठीक लगती है कि यह स्टेट का मामला है। मैं तो कहूंगा कि ऐसे जहां मामले हों, वहां बाबू जी को पूरा अख्तियार दिया जाय। अब्बल तो मैं उन आदमियों में से हूं जो ज्यादा अरसे तक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमें ठीक कीमत नहीं मिलती और आए साल किसान को एजीटेशन चलाना पड़ता है चाहे वह आन्ध्र प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरा कोई प्रदेश हो, आए साल जो आदमी जमीन को काश्त करे, अपना खून पसीना उस में लगाए, गन्ना तैयार करे वह इस के लिए एजीटेशन करे और फिर जेल में जाय। यह हम नहीं चाहते कि आए साल यह आन्दोलन चले और इस का एक बार फैसला किया जाय कि किसान को क्या दाम मिलना है और जो आप मुकर्रर करें वह लागू कर दीजिए। साल दो साल के लिए या आगे तक के लिए उसे लागू कर दीजिए। अगर कोई उसे फालो नहीं करता है चाहे वह मिल मालिक हो या कोआपरेटिव वाले हों जो भी इस को फालो न करें उन को आप ब्लैक लिस्ट करें, उन का लाइसेंस कैंसिल करें।

दूसरी बात—यह जो कमीशन मुकर्रर किया जाता है प्राइसेज का इस में सारे ही गैर-किसान भर दिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कई एम० पी० भी हैं एक से एक अच्छे किसान उन में बैठे हैं, दूसरे लोग भी हैं किसान-वायस के, तो जहां किसान के खेती का सवाल है चाहे गन्ने का हो या कोई हो, उस में उन को रखें। यह जो एक्सपर्टस हैं, बुक-वर्म्स हैं, इन को कुछ पता नहीं होता है। वह कार्ल मार्क्स और ऐंजिल्स की बात तो रट लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि किसान की खेती में जो पैदा होता है, किस फसल का या किस पेड़ का नाम क्या है और कौन सा अनाज कहां और कैसे पैदा होता है, यह भी उन्हें पता नहीं होता है। तो उस में ऐसे लोग लिए जाएं जो किसान के प्रतिनिधि हों।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, हमारी तो हर एक चीज पर सीलिंग हो गई, जमीन पर भी सीलिंग लगा दी, कीमत पर भी सीलिंग लगा दी और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी सीलिंग है, हम अपना गुड़ हरयाने से दिल्ली नहीं ला सकते, दिल्ली से यू० पी० नहीं ले जा सकते। हर-एक जगह सीलिंग और घेराव हमारे लिए है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिरला, टाटा और शहर में रहने वाले जो हैं उन पर भी सीलिंग लगे। देहात में तो आप ने सीलिंग लगा दी गरीब किसानों पर लेकिन इनके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। खैर, वह तो दूसरी बात है। वह तो पता नहीं कब आप लगाएं लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कि जहां ईख की कीमत है, या शुगर की है या और दूसरे ग्रेन्स की कीमत है वहां तो आप ने प्राइस मुकर्रर कर दी लेकिन किसान जो चीज खरीदता है उस को लोहे की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसी चीजें हैं जिन की उस को अपने ऐग्रीकल्चर में इस्तेमाल के लिए जरूरत पड़ती है, वह उसको बड़ी महंगी मिलती हैं। एक आदमी इतनी मेहनत से जो चीज कमाए उस की कीमत तो उसे थोड़ी मिले और दूसरी जो चीज वह लेने जाय, उस को वह महंगी मिले, तो पैरिटी आफ प्राइसेज होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी का भाव तो जो होता है वह होता ही है, गन्ना जो कारखाने में ले जाते हैं उस से मोलेसेज निकलता है। वह गवर्नमेंट दे देती है बड़े बड़े ठेकेदारों को। उस को की मार्केट में बेच दें और वही किसान को कीमत देने में सप्लीमेंट कर दें तो इसी से उस के भाव बढ़ सकते हैं। इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

16 44 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

तीसरी चीज, यू० पी० में, हरयाने में, पंजाब में सारी जगह ही यह बेचारे किसान जाकर थोड़े दामों में अपना गन्ना बेचते हैं और बेचने के बाद तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच और छः-छः महीने तक उस को पैसे ही नहीं मिलते । बड़ी मुश्किल से कर्ज ले कर वह इस में लगाता है, इधर उस का सूद चढ़ता जाता है और उधर उस को वहां से पैसे नहीं मिलते, मिल मालिक उस पैसे को सट्टे में और दुनिया भर की चीजों में लगा कर उस से और पैसे बनाते हैं । इन सरमायेदारों के ऊपर करोड़ों रुपये एरियर बाकी पड़ा है । तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पैमेंट नहीं करते ऐसे लोगों पर कम्पाउंड इन्टेरेस्ट लगाकर वह पैसा उनको वापस दिलाया जाय। आखिर वह भी तो कर्ज का पैसा लगाते हैं, इधर वह कर्ज देने वाला उस की खाल खींचता है और उधर वह उस को पैसे नहीं देते हैं । तो जब उसे कोई लाभ ही नहीं है तो वह क्यों अपना गन्ना मिलों को दे ? मैं आखिर में कहना चाहूंगा, अब वक्त आ गया है, किसान बहुत सयाना हो गया है । किसान बहुत सयाना हो गया है, वह समझता है कि किस चीज के बोने में फायदा है, मिर्च बोने में फायदा है या गन्ना बोने में फायदा है या कपास बोने में फायदा है या गेहूं बोने में फायदा है, लेकिन अब वह ज्यादती की बरदाश्त नहीं करेगा । यहां के ब्लैक मार्केटियर, जखीरेबाज लोग चीनी खाय, स्मगलिंग करें और फायदा उठायें, लेकिन उस की जच्चा को भी चीनी न मिले, यह चीज अब उसे बरदाश्त नहीं होगी।

जो लोग आज चीनी के मामले में बहुत हिमायत करते हैं, मैं उन से कहना चाहता हूं—अगर चीनी चाहिये तो किसान को ठीक कीमत दो, नहीं तो जैसे आपने हम पर कन्ट्रोल लगा दिये हैं, उसी तरह से चीनी पर भी कन्ट्रोल लगाइये । मैं देहाती आदमी हूं, इन बातों को ज्यादा नहीं जानता कि कन्ट्रोल में फायदा है या डी-कन्ट्रोल में फायदा है, लेकिन हमारे लिये डबल-स्टैण्डर्ड क्यों किया जाय । चीनी पर भी उसी तरह से कीमत का कन्ट्रोल लगाइये. उनको हद से ज्यादा मुनाफा नहीं मिलना चाहिये ।

एक चीज मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आज 80 फीसदी लोग देहातों में बसते हैं, बेहतरीन किसान, गरीब हरिजन, आदिवासी भाई—हिन्दुस्तान का बेहतरीन चेहरा देहातों में है, इसलिये कम से कम 70 फीसदी—मिलनी तो 85 फीसदी चाहिए. 85 न मिले तो कम से कम 70 फीसदी चीनी उन को मिलनी चाहिए । आज हो क्या रहा है—जो नाज पैदा करे, उस को नाज नहीं मिलता, जो कपास पैदा करे, उस को कपड़ा नहीं मिलता, जो गन्ना पैदा करे, उसको चीनी नहीं मिलती, यह क्या गोरखधन्धा है । क्या हम इन्सान नहीं हैं ? मैं आपकी मारफत अपने माननीय नेता से कहना चाहूंगा कि देहातों के लिये भी चीनी का कोटा मुकर्रर करो । ये ब्लैक-मार्केटियर जो दुनिया भर का पैसा कमाते हैं, इन को चमचम, पेड़े, इमरती खिलाने वाला कौन है ? हमारे देहात में किसान, हरिजन भाई उन के लिए मेहनत करके गन्ना पैदा करते हैं, लेकिन उन को खुद को चमचम, पेड़े और इमरती खाने को नहीं मिलती. क्या वह घटिया किस्म के इन्सान हैं । उन को भी चीनी का कोटा मिलना चाहिये, ताकि हमारे यहां की औरतें भी इन चीजों को बनाना सीख सकें ।

एक बात मुझे यह अर्ज करनी है कि ये जो बीच के बिचौलिये हैं—मिडिल मैन—दे मस्ट गो । ये कहते हैं कि टिलर आफ दी सायल को जमीन मिले, लेकिन मिडिल मैन को भी बीच में से हटाना उतना ही जरूरी है । आज जो किसान गुड़ बना

[श्री रणधीर सिंह]

कर मण्डी में ले जाता है, जितना वह कमाता है, उस से दुगुना और तिगुना ये बीच के कमीशन एजेन्ट्स खा जाते हैं। मैं चाहता हूं कि स्टेट और किसान का सीधा ताल्लुक हो और जो बीच में कमाते हैं, उन से लेकर किसान को इन्सेन्टिव दिया जाय—कीमतों के मामले में।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं—यह जो तजबीज आई है कि इस को एक प्लांटेशन समझा जाय—यह मुझे बड़ी अच्छी तजबीज लगी। जसे टी-बोर्ड है, काफी बोर्ड है, उसी तरह से मको भी कारपोरेशन या शुगर-केन-बोर्ड कहा जाय और इस के डवेलपमेन्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्सेन्टिव—पानी का, बिजली का, प्राइसेज का दिया जाय। मैं तो यह भी चाहूंगा कि उस को फी मूवमेन्ट का भी हक हासिल हो, वह जहां चाहे अपनी चीज को ले जाय। किसानों से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन रात को अपने गुड़ को उसे जो स्मगल करना पड़ता है, उस के मूवमेन्ट को आप बन्द कर देते हैं, यह मुनासिब नहीं है। यह विधान के भी खिलाफ है, एक आदमी को फ्रीडम होनी चाहिये कि वह अपनी चीज को जहां चाहे ले जाये। आज देश को किसानों की बड़ी जरूरत है, हर चीज में जरूरत है, फौज में भेजने के लिये, देश को बाहरी हमले से बचाने के लिए और उस से भी ज्यादा देश को फीड करने के लिए उस की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिये कि जिससे किसान फील करे कि उस के साथ डिस्क्रीमिनेशन हो रहा है। आज उस को उस के प्रोडक्ट की सही रिटर्न नहीं मिल रही है।

मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को नोट किया जाय और किसान को जितना ज्यादा से ज्यादा इन्सेन्टिव आप दे सकते हैं, आप दें। अब सीजन आ गया है, जगह जगह जोन जाने के लिये फौजें तैयार हो गई हैं, यू० पी० में भी मैंने सुना है और मेरी स्टेट में भी तैयारी हो रही है। लेकिन उस फौज के सिपहसालार आप हैं, वे आपकी तरफ टकटकी बांधे बैठे हैं, इसलिये आप इस की कीमत मुकर्रिर कीजिये, मुकर्रिर ही नहीं, बल्कि उन को दिलवाइये। पिछली दफा आप का हुकम स्टेट्स ने नहीं माना, वे समझते हैं कि कीमत सेन्टर मुकर्रिर करेगा, लेकिन इन्होंने देना नहीं है, यही वजह है कि उन्होंने नेशकर बोना बन्द कर दिया है, जिससे हमें फौरन एक्सचेंज में भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिये उन को ज्यादा से ज्यादा इन्सेन्टिव मिलना चाहिये।

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, अभी जो स्वतन्त्र पार्टी के वक्ता भाषण कर रहे थे—उनसे अच्छा वकील कोई सरमायेदारों का नहीं हो सकता और जाहिर बात है कि वह जिस दल के प्रतिनिधि थे, उनका उस भाषा में बोलना ठीक ही था। तकरीबन उसी किस्म की बात हमारे जनसंघ के सदस्य ने की। बात यह है कि हमारे देश में शुगर की नीति क्या हो—गन्ने के दाम, चीनी का दाम, इसकी मिलों का रुख या इस उद्योग को इस देश में बचाने के लिये कौन से कदम उठाये जायें—ये प्रश्न हमारे विचाराधीन हैं।

अगर आप मिल वालों को देखें तो वे कहते हैं कि हम बराबर घाटे में जा रहे हैं। किसानों को देखें तो उन की यह शिकायत रहती है कि हम को गन्ने का ठीक दाम नहीं मिलता है और हमारी सरकार की तो कोई नीति ही नहीं है—जैसी यह हर क्षेत्र में दिवालिया है, वैसी ही इस क्षेत्र में भी दिवालिया है। कभी कहते हैं कि रिकवरी कम हुई है, कभी कुछ कहते हैं—लेकिन अगर इस देश में इस उद्योग को बचाना है तो कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी—इस देश में इस गन्ना उद्योग को कैसे बचाया जाय, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जहां 78 मिलें हैं। वहां के काश्तकारों को 7 रु० 37 पैसा फी क्विंटल दाम दिया जा

रहा है । हमारे भाई रणधीर सिंह ने ठीक ही कहा है—हमारे यहां कहावत है—अन्धेर पुर नगरी अन्धेरपुर राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा । दाम की कोई नीति ही नहीं है, जिस भाव लकड़ी बिकती है, वही दाम गन्ने का है—यह कहावत बिलकुल ठीक चरितार्थ होती है ।

हमारे स्वतन्त्र पार्टी के भाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों को अच्छा कपड़ा दें—ये खाण्डसारी किसानों को नहीं खिलाना चाहते हैं, शुगर खिलाना चाहते हैं । हकीकत यह है कि ये किसानों को नंगा कर के करोड़ो रुपया लूटने वाले इस तरह की चमत्कारिक भाषा में बोल कर सब को समझाने की कोशिश करते हैं कि चीनी की मिलें अच्छा काम कर रही हैं । लेकिन श्रीमानजी, इस सम्बन्ध में बहुत सी रिपोर्टें पेश हो चुकी हैं—मेन रिपोर्ट है, कुण्डू राव रिपोर्ट है—इन रिपोर्टों में कहा गया है कि इन प्राइवेट धन्धों ने कई गुना देश को लूटा है, अच्छी तरह से लूटा है । मैं उन के विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन इन रिपोर्टों में बताया गया है कि किस तरह से देश को बरबाद किया गया है । आज जो गन्ना मिलें हैं उन की जमींदारी कायम है, न हम उन इलाकों में चूल्हे लगा सकते हैं, न कोल्हू लगा सकते हैं, न गुड़ बना सकते हैं, पूरे का पूरा एरिया इन मिलों के लिये रिजर्व है और किसान मजबूर होता है कि उन मिलों के हाथ अपने गन्ने को बेचे और वे चाहते हैं कि जितनी कीमत गिर जाय, उतना अच्छा है । आप बता दीजिये क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो घाटे में रोजगार करेगा ? इनकी कारें, इनकी मोटरें, इनके बंगले कहां से चलते हैं, अगर मिलें घाटे में हैं ? आप बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में जाकर देखिये, मिल वाले ऐश करते हैं और किसानों का 6 करोड़ रुपया हजम कर के बैठे हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं ।

दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर सरकार ले लेगी तो कैसे चलेगा ? हम कहते हैं कि अगर प्राइवेट के हाथों में ये मिलें चलती हैं तो सरकार के हाथ में लेने से क्यों नहीं चलेंगी ? सरकार नहीं चलायेगी, तो जैसा बहुत से भाइयों ने कहा—कोआपरेटिव्ज को दे दीजिये ताकि सही मायनों में हमारे देश में इस उद्योग का विनाश न हो । लेकिन यह सरकार तो इन के विनाश पर तुली हुई है, कोई भी कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 अक्तूबर, को प्रस्ताव पास किया और कहा कि सीजन से पहले मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये । हमारे स्वतन्त्र पार्टी के भाई ने कहा कि यहां की सरकार कहती है कि स्टेट की सरकार ले ले और स्टेट की सरकार चाहे तो केन्द्र के कन्सर्न को ले ले क्या उल्टी बात है । यह तो संवैधानिक प्रश्न है । केन्द्र की सरकार ले सकती है या नहीं ले सकती है—यह तो वैधानिक प्रश्न है, लेकिन इन्होंने इस को उल्टा लिया, क्योंकि सी० बी० गुप्ता हमारे सूबे में सब से ज्यादा शुगर मिल वालों से पैसा ले कर आज पूरे संगठन को चला रहे हैं । इसलिये उन्होंने साफ तौर से इन्कार किया कि हम शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे । जब कि पूरी कैबिनेट का वडिक्ट था कि मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, लेकिन चूंकि इस में इन का निजी स्वार्थ है इसलिये उस को नहीं करना चाहते । लेकिन उन की बात यहां पर कोई नहीं करता और ऊपर से यह कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट ले ले । यह पार्लियामेन्ट सोवरिन-बाडी है, हमें इस बात का अख्तियार है कि हम चाहें तो उनका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि इसमें कोई बाधा नहीं है, यह तो एक नीयत का प्रश्न है । अगर आप इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, तो ये मिल वाले कभी आपसे नहीं कहेंगे । क्या समाजवाद इस

[श्री सरजू पाण्डेय]

तरह से आया करता है, जब आता है तो ये लुटेरे जेलखाने में बन्द होते हैं, यहां इस सदन में बैठ कर भाषण कर के, लच्छेदार बातें कह कर समाजवाद नहीं आया करता। हमारे यहां बिहार में हड़तालें हुईं—न सड़कें बनवाते हैं, गन्ने की तौल में लूटते हैं, मोलेसेज में लूटते हैं। श्रीमानजी, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारा किसान शीरा पीकर जीता है।

75 प्रतिशत आदमी आषाढ़ के महीने में एक रुपए का एक किलो शीरा खरीद कर खाते हैं और सारा का सारा मुनाफा ये लोग लूट कर खाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम तो परेशान हैं। कई बार इस प्रश्न को लेकर हड़ताल हुई और आगे भी हो सकती है। हम आपसे मिले और कहा कि गन्ने का दाम बढ़ाइये, सात रुपए क्विंटल का दाम उचित नहीं है। पिछले साल भी पंजाब और उत्तर प्रदेश में कम कीमत मिली। आज वहां के किसान परेशानी में हैं। सात रुपए क्विंटल का दाम देने से किसानों की लागत भी नहीं निकलती है। खाद का दाम आपने बढ़ा दिया है, बिजली के चार्जेज बढ़ गए हैं, लेबर के चार्जेज बढ़ गए हैं। किसानों का घाटा कैसा पूरा होगा? अगर सही मानों में उनको लागत का खर्चा भी नहीं मिलेगा तो फिर खेती का क्या हाल होगा? इसीलिए हम आपसे मिले, प्रधान मन्त्री से मिले और यह कहा कि गन्ने का दाम बढ़ाइये लेकिन यह कह दिया गया कि रिकवरी कम हो रही है और मिल वालों को घाटा जा रहा है। मैं पूछता हूं कि रिकवरी कौन तय करता है? इसके लिए कोई अलग से एथारिटी नहीं बनी हुई है। रिकवरी तय करने वाले उन्हीं के आदमी होते हैं। ज्यादा हुई तो भी कम बता दी। वे लोग चार-चार खाते रखते हैं और एक चोरी का रखते हैं जिसका किसी को भी पता नहीं होता। एक बार इस सदन के सदस्य ने एक मिल की बैलेंस शीट चुरा ली और कहा कि अगर हम को पैसा नहीं दोगे तो मैं इसको पार्लियामेन्ट में पढ़ूंगा। इसलिये अगर आप सही मानों में समाजवाद लाना चाहते हैं तो फर्म कदम उठाइये—सारा देश आप के साथ है, हम भी आपका समर्थन करेंगे। लेकिन मिल मालिकों की आड़ में इस चीनी उद्योग को बर्बाद न कीजिये। दो करोड़ आदमी और हजारों मजदूर इस उद्योग में लगे हुए हैं—वे सब बर्बाद हो जायेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इससे पहले कि किसान हड़ताल पर जायं और झगड़े में पड़ें, आप गन्ने का दाम कम से कम दस रुपया कर दीजिये ताकि किसानों की जिन्दगी की रक्षा की जा सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have got hardly half-an-hour out of which the Minister also will take sometime to reply. So, if you all agree, I would finish the list of different groups, and if there is time, I will give chance to one or two more from the Government side.

SHRI RANGA (Srikakulam) : Where is the time?

MR. DEPUTY-SPEAKER : If there is time; there are different groups who have not spoken yet. They must be given a chance. In any case the Minister will reply on behalf of the Government. So, I would request Members on this side to kindly understand the position. (*Interruption*) I am only making a general request. Everything possible will be done within the time available. Shri Umanath.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, even at the beginning, at the point of formulating this partial decontrol policy, our party had made its position clear, that the purpose of this policy of partial decontrol was to enable the sugar magnates to loot the public as well as the cane growers and to legalise the black market in sugar; that is, the black

market prices in sugar. The Government did not agree; they said no, and they said that the partial decontrol was to enable the sugar magnates to pay higher prices to the cane-growers and that the losses that they would incur by the higher prices would be made up by allowing the sugar magnates to sell at that rate in the open market. So the higher amount that they would get by the sale in the open market will make up for the losses that they would be incurring in respect of the sugarcane growers. That was the explanation of the Government and the employers' contention was two-fold. One was about the higher price to the cane-growers; the other was, there was absolutely no margin of profit in the levy price fixed by the Government. In fact, they were incurring losses, according to the employers. So, in order to make up that loss and the loss arising out of the payment of higher price for the cane-growers, this open market was permitted. According to the Government after payment to the cane-growers, and according to the employers after overcoming the losses through the levy sugar, their profits were to be nominal, and nothing more than that. Now, after that announcement of policy, the balance-sheet has come out. When 60 :40 was declared. the balance-sheet, apart from the hidden wealth, has shown that many of the factories have made profits after payment to the cane-growers at the prices fixed; not twice. Their profit was not twice or thrice but six times what it was the previous year, when it was completely controled. On the eve of that season, on 17-12-68, the *Amrita Bazar Patrika* said :

> "According to the latest balance sheets of the sugar companies, the Western and Southern Mills profited from the decontrol operating since last year, some of them even doubling their profits over the previous year."

17 Hrs.

They have thus generated huge profits. The balance-sheets have believed the contention of the employers that higher cane price was causing hardship and also the Government's contention that after paying a higher price to the growers, the profit would be nominal.

At least after this, I thought Government would change the policy, but they did not. They said, we will reduce the amount of open market sugar from 40 to 30 per cent. After this modification, what is the present position ?

Oudh Sugars, a company run by Birlas, which made a profit of Rs. 64 lakhs when it was 60 : 40, has made a profit of Rs. 143 lakhs now when it is 70 : 30, *i.e.* an increase of 122 per cent. D.S. &. A. Company under Parry Company, which normally makes a profit of about Rs. 10 lakhs, made a profit of Rs. 74 lakhs when it was 60 : 40 and has made a profit of Rs. 95 lakhs, when it is now 70 : 30. Even after this, the Government say that they will continue the 70 : 30 policy. Is it not obvious that this policy of partial decontrol was purely to enable the sugar magnates to loot the public and the growers ?

Last time, the Minister said that in no place the growers are paid less than Rs. 100. He was challenged and when Madras was cited, he said, in Madras, they have paid less because the State Government asked for permission from the Centre, which was given.

SHRI S. KANDAPPAN : That was an emergency condition, when a large acreage was standing without being cut. The farmers were desperate. That is why Government permitted it.

SHRI UMANATH : The *Amrita Bazar Patrika* said in 1968 :

> "Most probably the cane price is nearing its end. Cane is now available in plenty in most of the areas at prices below Rs. 10 per quintal.
>
> The Western Mills in spite of high recovery between 12 and 20 per cent, have contracted cane purchases at a price less than Rs. 10 per quintal."

So, in many places the growers are paid less than Rs. 10. The employees and workers are still receiving the wages fixed in 1960. The public have been fleeced. All this is due to partial decontrol, which has enabled the sugar magnates to make such huge profits. Now when open market prices have come down a bit, the employers are

[Shri Umanath]

raising a huge furore saying, they are going to discontinue it.

The only solution is this. It is time that not only the U.P. sugar industry is nationalised, but the industry as a whole throughout the country should be nationalised by the Central Government. If they say that the State Government should do it or U.P. Government can do it, I will only say, they are playing politics, because the State Government cannot pay compensation to the factories which are nationalised. This is playing politics. So, I say that this question of playing politics should not be there and that the sugar industry must be nationalised. After so much of exposure of the failure of partial de-control, it must be given up.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ): देश में चीनी का संकट अचानक नहीं आता है। हर साल मिलों की तादाद बढ़ती जा रही है, मिलों की क्षमता बढ़ती जाती है लेकिन चीनी हर साल ज्यादा पैदा नहीं होती है। हर पांच साल का एक चक्र बना हुआ है। संकट आता है, दो साल उसके निवारण में लगते हैं और दो साल नया संकट बुलाने में लगते हैं। पिछली बार क्यों ऐसा हुआ, क्या कभी इस पर सरकार ने गौर किया है। ये पांच साला चक्र क्यों बने हुए हैं। चार क्राइसिस आ चुके हैं। और आज मैं फोरकास्ट करना चाहता हूं कि अगर चीनी और गन्ने के बारे में आपकी नीति नहीं बदली तो दो साल के बाद अगर पच्चीस लाख टन से ऊपर चीनी आप बना लोगे तो मुझे कहना कि क्या बोल रहे थे। पांचवां संकट दो साल के बाद आने वाला है।

पिछला संकट जो आया उसको आप देखें। पूरा हिन्दुस्तान का औसत अगर आप लगायेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान को औसतन पांच रुपये क्विंटल से ज्यादा दाम मिनिमम दामों से नहीं मिले। कहीं पर पांच रुपये से कुछ कम और कहीं पर पांच रुपये से कुछ ज्यादा मिले। लेकिन औसतन पांच रुपये क्विंटल से ज्यादा नहीं मिले। अब आप देखें कि दस क्विंटल गन्ने में एक क्विंटल चीनी निकलती है, दस सैकड़ा के हिसाब से निकलती है। पचास रुपये फी क्विंटल चीनी पर किसान को दिया गया और 250 रुपये फी क्विंटल तेज दाम पर चीनी को बेचा गया। इस वास्ते मिल मालिकों का हित इस में है कि चीनी का संकट आए और उनको फायदा हो। चीनी ज्यादा बने तो कभी उनको फायदा नहीं होता है। सरकार की पालिसी अब तक उनके हाथ में खेलने की रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब यह कहते हैं कि पार्शल डिकंट्रोल आपका बहुत अच्छा रहा है, यह बहुत अच्छी चीज है तो क्या आप पूरे हिन्दुस्तान में एक सिंगल शूगर फैक्ट्री भी बता सकते हैं जो कि इस पार्शल डिकंट्रोल के मातहत किसान को 7 रुपये 37 पैसे के बजाय 7 रुपये 38 पैसे दे रही हो, एक नया पैसा भी फाल्तू दे रही हो। कोई कोओपरेटिव फैक्ट्री हो सकती है जो दे रही हो लेकिन कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री नहीं दे सकी है।

दो साल हम को चाहिये होते हैं गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए और एक साल पहले गन्ने का प्लानिंग होना है। फिर जा कर कहीं गन्ने की फसल हम ले पाते हैं। इस साल तो हम देख रहे हैं कि चालीस लाख टन चीनी होगी और यह ठीक भी है, इस में कोई दो राये नहीं हैं। दो साल पहले गन्ने का तेज भाव था। इसलिए किसानों ने ज्यादा बोया। लेकिन मैं आप को बता सकता हूं कि अगले साल क्या होने जा रहा है। अगले साल तीस लाख टन से ज्यादा चीनी पैदा नहीं होगी और उससे अगले साल 22 लाख होगी। फिर पार्शल डिकंट्रोल होगा, 18 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम होगा, फिर पैदावार गन्ने की ज्यादा बढ़नी शुरू होगी, उसके बाद फिर संकट पैदा होगा। क्यों आप मजाक करते हैं किसानों के साथ। मिनिमम प्राइस आप को इतनी जरूर देनी चाहिये जिससे पड़ता खा जाए। गवार की तरह यह सरकार भी गन्ना नहीं भेली देती है। दस रुपये क्विंटल मिनिमम भाव तय नहीं करती लेकिन कभी-कभी अठारह अठारह रुपयें दे देती है। मैं

चाहता हूं कि एक दफा आप पालिसी को तय कर लो।

श्री कंडप्पन ने जो कुछ कहा है उसका मैं थोड़ा सा समर्थन करता हूं। हमें धरती पर उतर कर सोचना चाहिये। इस देश में गन्ने की सब से अच्छी पैदावार महाराष्ट्र में होती है। वहां टनेज भी ज्यादा है 14 और परसेंट के करीब शूगर कटेंट निकलता है। दूसरा नम्बर साउथ का आता है जहां शूगर ज्यादा निकलती है। उत्तर भारत कम्पीट नहीं कर सकता है उनके साथ। किसी जमाने में हमारे यहां 70 परसेंट चीनी पैदा हो रही थी और आज घट कर तीस प्रसेंट पर हम आ गए हैं। यही हालत रही तो हम कभी कम्पीट नहीं कर सकेंगे। उत्तर भारत का इलाज क्या है। इलाज चुकन्दर की खेती है। वह आज शुरू हुई है। जब हम मंत्री महोदय से कहते हैं तो वह हमारी बात नहीं मानते हैं। हमने बिल इंट्रोड्यूस किया था कि चुकन्दर का भी मिनिमम भाव तय कीजिये। लेकिन आप वह नहीं कर रहे हैं। चुकन्दर से गुड़ नहीं बनता है। चुकन्दर की अगर आप मिनिमम प्राइस तय नहीं करेंगे तो कभी इसकी खेती उत्तर भारत में नहीं होगी। उससे गुड़ नहीं बनता है। गन्ने से गुड़ बनता है।

चुकन्दर को बढ़ावा देंगे तो डिफ्यूजन प्लांट लगेंगे। चुकन्दर के लिए डिफ्यूजन प्लांट होता था। अब गन्ने का भी प्लांट बन गया है। इसलिए चालू करेंगे हम गन्ने पर और खत्म करेंगे चुकन्दर पर। फिर दक्षिण के साथ कम्पीट कर सकेंगे। अगर आप चुकन्दर के मिनिमम भाव तय नहीं करेंगे तो जितनी इधर की फैक्ट्रियां हैं ये सब उजड़ जायेंगी।

मिलों के ऊपर झगड़ा चल रहा है कि उनका क्या होना चाहिये। दस लाख का जो प्लांट किसी जमाने में खड़ा किया गया था वह आज बूढ़ा हो गया है। पचास साल पुराना हो गया है। गुप्त जी कहते हैं कि ये सिक मिल्ज खड़ी हैं। लाशों का इलाज होना चाहिये।

जैसे शहरों में पुराने मकान हो जाते हैं और उनके गिरने का डर होता है और म्यूनिसिपैलिटी उनको गिरवा देती है ठीक इसी तरह से सरकार इन लाशों को भी गिरवा दे। इनको लेने से कोई लाभ नहीं है। कोओपरेटिव मिलें खड़ी की जायें। जब हम कहते हैं कि राम सुभग सिंह जी, तुम को लोग सिंडीकेट कहते हैं, तुम स्वतंत्र जन संघ के साथ रहते हो, तो वह कहते हैं कि इन्दिरा जी तो समाजवादी हैं लेकिन हम सुपर समाजवादी हैं। उनकी बात पर मैं यकीन कर लेता हूं। उनकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अब सुपर समाजवादी का फर्ज हो जाता है कि वह तत्काल काम करे। 1972 नजदीक आ रहा है। सुपर-समाजवादी कब तक इस तरह से बैठे रह सकते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीयकरण करेंगे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ जो गन्दी मिलें हैं उनको खत्म करो। बाकी का राष्ट्रीयकरण करो और राष्ट्रीयकरण करने के बाद चाहो तो को-ओपरेटिव्ज में बदल दो। गुप्त जी लोगों की आंखों में धूल झोंकते नहीं जा सकते हैं। ढाई-ढाई रुपये के हिसाब से बिकने वाला जो आयरन स्क्रैप है, उसको वह किसानों के गले पर लाखों रुपये में बांध दें, ऐसा हम नहीं होने देंगे। मैं आशा करता हूं कि जो सुपरसमाजवादी हैं वे जरूर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करके सुपरसमाजवादी होने का सबूत दें।

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, an unchecked exploitation of the sugarcane growers in the country has gone on for quite some time. A government, which shows concern towards the kisans of the land, ought to tailor its policies so as to subserve broadly the interest of the sugarcane growers. Not only has the private sector exploited them but I am not going to condone the part that the Government has played in that exploitation. Let me add that they are abettors in that exploitation.

[Shri S. M. Krishna]

When Shri Jagjiwan Ram was approached by newsmen in Lucknow in the month of September and was put the question, "Why not nationalise the sugar industry in the country?", being a very seasoned statesman in this country he said, "Let sugar retain its sweetness." That was a cryptic reply and he did not elucidate it further. I would like to pose a simple question. Because you are going to nationalise the sugar industry, does sugar lose its sweetness? That is a question which Shri Jagjiwan Ram has to answer.

Shri Umanath has made a very strong case as to how politics should not be played with this. Last year when there was a debate like the one we are having today, I posed the problem that there had to be a certain uniform approach to the fixation of sugarcane price at least in given areas. I come from a constituency where there are two sugar factories already and a third one is coming up in the private sector much to my dislike. One of them is run by the co-operative effort and the other one is run by a joint stock company in which the Government of Mysore has the controlling interest. In the year 1968 when the sugarcane grower got the maximum in this country in the co-operative sugar factory the canegrower got Rs. 12 a quintal whereas in the Government controlled joint stock company the sugarcane grower got just Rs. 7 or Rs. 8 a quintal. Shri Jagjiwan Ram knows it. I had the privilege of making a personal representation to him when he visited my constituency. These two sugar factories are situated in a radius of eight miles. What is the rationale or logic behind this great disparity in price in a radius of eight miles? The sucrose content is almost the same in both these areas. Therefore I repeat the suggestion, which I have made before, that there has to be a certain uniform rate structure of sugarcane in a given area at least.

I am not going to compare the north and the south still I would like to commend the argument put forward by Shri Kandappan that greater emphasis has to be given down south because there is a greater potential for the expansion of the sugar industry down south.

Since you are rushing towards the bell and I would not like to embarrass you, I would add my humble voice to the demand that the sugar policy has to be reviewed in the light of certain revelations made and the policy has to be revised so as to subserve broadly the basic interest of the sugarcane growers in this country; towards that direction we have to go about thinking in terms of nationalising the sugar industry in the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Raghuvir Singh Shastri; only 2 minutes.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत): तो, उपाध्यक्ष महोदय, रहने दीजिए । जिन मदस्यों को आप ने दस मिनट दिये, वे पंद्रह मिनट तक बोले । और मुझे आप केवल दो मिनट दे रहे हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have to conclude it at 5-30 P.M. The Minister must also have some time to reply. You would like to hear the Minister also.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री: मुझे अपनी बात कहने के लिए थोड़ा समय दीजिए ।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I have to move my motion at 5-30 P.M.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह चीनी उद्योग का मामला ऐसा है, जो हमेशा किसानों और मिल मालिकों के बीच रस्सा-कशी का विषय रहा है । किसान हमेशा यह समझते रहे हैं कि उन के साथ अन्याय हो रहा है और उन के हित सुरक्षित नहीं हैं । उदाहरणस्वरूप 9 दिसम्बर, 1968 को हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने संसद् में कहा कि गन्ने का दाम दस रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए । उस के बाद इलैक्शन्ज में भी खाद्य मंत्री महोदय ने जगह-जगह जा कर यह घोषणा की । लेकिन 11 मार्च को, जब इलैक्शन खत्म हो गये और मिनिस्ट्रीज बन गई, उन्होंने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैंने तो यह कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन यह मेरा कोई आश्वासन नहीं था । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के स्तर पर ऐसी बात हो, यह उन्हें शोभा नहीं देता है । मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि श्री जगजीवन

राम किसानों के शुभचिन्तक हैं, परन्तु मंत्री होने के नाते वह ऐसी भाषा में बोलें, इस से किसानों को दुख होता है।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। हम वहां पर चीनी मिलों के राष्ट्रीकरण की मांग क्यों कर रहे हैं; एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें लाश बन चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब तो वे लाश हैं, इस लिए अभी तो उन को उठाया जा सकता है, उन का क्रियाकर्म किया जा सकता है, लेकिन अब उस लाश में कीड़ा पड़ने वाला है, तब कोई उस का क्रियाकर्म करने वाला नहीं होगा। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोई मिल तभी इकानोमिक कही जा सकती है, जब वह प्रतिदिन 1250 टन गन्ना क्रश करे। लेकिन यू० पी० में 71 में से 37 मिलें ऐसी हैं, जो 1250 टन से कम गन्ना प्रति दिन क्रश करती हैं। 12, 14 मिलें तो बराबर बीमार हैं। उन में से दो मिलें जिला मेरठ में बीमार हैं। एक मिल तो ऐसी बीमार है कि उस को कोई दवा नहीं दी जा रही है।

हम कई दफा डेपुटेशन ले कर खाद्य मंत्री महोदय से मिले हैं। उन्होंने 24 जुलाई, 1969 को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यू० पी० में किसानों का आठ करोड़ रुपया मिलों पर बकाया है और उन मिलों पर पांच करोड़ के सरकारी टैक्स भी पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों के रुपये और टैक्स के रुपये की अदायेगी के लिए क्या इन्तजाम किया है। जब हम उन से मिलते हैं, तो वह ऐसी भाषा में बात करते हैं जैसे वह इस बारे में असमर्थ हैं, हैल्पलेस हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं।

यू० पी० में उत्तर प्रदेश में 12, 14 मिलें बीमार हो चुकी हैं और दो चार साल में सारी मिलें बीमार हो जायेंगी और उन के मालिक उन को छोड़ कर भाग जायेंगे। तब भी तो सरकार को ही उन्हें सम्भालना पड़ेगा। इस लिए हम चाहते हैं कि उन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। लेकिन राष्ट्रीयकरण से हमारा मतलब यह नहीं है कि उन पर सरकारी अफ़सरों को बिठा दिया जाये, क्योंकि हम ने यह देख लिया है कि जहां अन्य मिलों में 9.4 परसेंट रीकवरी है, वहां अमरोहा की सरकारी मिल की रीकवरी केवल 7 परसेंट ही है। हम तो यह चाहते हैं कि जब सरकार इन मिलों को ले, तो वह उन के प्रबन्ध में किसानों को प्रतिनिधित्व दे, किसानों से किश्तों में रुपया ले कर उन्हें उन मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था में अधिकार दे।

खाद्य मंत्री महोदय कहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। जब भूमि पर सीलिंग लगाने की बात आती है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जा सकता है, जो कि स्ट्रिक्टली एक स्टेट सबजेक्ट है, लेकिन चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कहा जाता है कि यह काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने भूमि पर सीलिंग के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, उसी प्रकार वह चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाये और हम देखेंगे कि कौन मुख्य मंत्री मना करता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister.

SHRI SHEO NARAIN: May I have 2 minutes only?

SHRI TULSIDAS JADHAV (Baramati): May I request you to give me 2 minutes only?

MR DEPUTY-SPEAKER: Kindly co-operate with me. We have to conclude it at 5-30 P.M. There are only 10 more minutes.

SHRI M. N. REDDY: This is an important discussion. You may extend the time.

SHRI TULSIDAS JADHAV : It is an important discussion. I will take only 2 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Kindly excuse me. Mr. Naidu is to move his motion at 5-30 P.M.

SHRI M. N. REDDY : It may be taken up at 5-45 P.M.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I cannot agree. It was allotted one hour. It has now been allotted half an hour only. Now you want to reduce it further.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us finish it soon. The hon. Minister.

SHRI RANDHIR SINGH : We can dispense with the half-an hour discussion today. This is a very important matter.

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE, AND LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI JAGJIWAN RAM) : Sir, the sugar Industry is an important industry of our country, especially for the people in the rural areas. In some States like Uttar Pradesh and Bihar, especially in North Bihar, sugar is the only industry. So it has a great impact on the rural population in certain parts of the country.

Sugar industry has gone through so many vicissitudes. Many members have complained about our sugar policy being an *ad hoc* policy. But nobody has been bold enough to suggest a permanent sugar policy.

AN HON. MEMBER : Nationalise the industry.

SHRI JAGJIWAN RAM : Everybody has suggested *ad hocism*. When I was going into the history of the sugar industry for the last 25 years, I found that it alternated between control, de-control, or partial control.

That has been the history. I had been taking with experts and factory-owners and I had a big conference with the cane growers' co-operative society officials and there also I said that it rotated between these three. Whether we can have a fourth solution nobody has been bold enough to come forward with a suggestion. What will be a long term sugar policy? If we decide that for 10 years we will have only control, then it will be a long term policy. If we decide that for the next 10 years we will have only de-control, then it may be a long term policy. But I am afraid it will not work. If there is full control, a situation will arise when we will have to partially de-control it or de-control it altogether. When there is de-control, some situation may develop when we will be forced to introduce control. It touches a large number of producers and also practically every citizen in the country as a consumer. So it is very difficult to have a long term policy. I am not ruling that out. When we reach the stage when you can continue a policy for 8 years or 10 years. I will welcome that.

SHRI K. N. PANDEY : You appoint a Committee of experts for this purpose.

SHRI JAGJIWAN RAM : I have consulted many experts and I have gone into the reports of many experts Committees. Sugar industry is the one industry where there have been many expert committees and all the outstanding experts who were available in the country had been associated with one or other of these committees. I have gone through them. I have spent much more time on this but I have not been able to find any solution.

SHRI M. N. REDDY : If time is given, I will suggest a long term policy. It is a very simple matter. Work with some imagination. If the Deputy Speaker has only allowed me time, I would have spelt out a long term policy.

SHRI SHEO NARAIN : Why are you shifting your responsibility? You should nationalise the sugar factories. Why are you playing this political game?

SHRI JAGJIWAN RAM : I am not that man who takes credit in saying 'I will monopolise all the wisdom of the entire world. It may be to my discredit, but I am frank to the House. I have not been able to find a long term policy. If anybody says 'It is very simple. This is the policy. Continue it for 20 years'—if that

is the wisdom, I am sorry for that wisdom. But that is not the solution. The simplest way one can suggest is : Fix a minimum price of sugarcane and let it continue for 10 years. But what are the consequences of that ?

When I introduced the policy of partial de-control, I am convinced that I did a good thing and it is. So, I have never said that the industry will not make a profit. Industry is not a charitable institution.

SHRI UMANATH : That was not the point.

SHRI JAGJIWAN RAM : I never said that they will not make a profit.

SHRI UMANATH : Only normal profits they will make. That is what was said by Mr. Shinde.

SHRI JAGJIWAN RAM : They are not charitable institutions. There are also all sorts of elements in the sugar industry which, given the opportunity, will reap abnormal profits and they have. I am not unaware of that. They have made unconscionable profits. I am aware of it. In the House I had admitted that. They made unconscionable profits. It should be for the Income-tax Department to mop up that abnormal profit that they have made. But there is no doubt that in 1967 cane-growers made profits, earned as much as they had never earned in the history of the sugar industry. In 1968 it is not as much as that; that is also a fact. But the sugar industry gained and sugar production went up. Growers have admitted that they were indebted for the last many years. It was in 1967 that they could wipe off the debt. And I am happy. That is due to that policy. I have got that figure to show how many crores they got. The industry also got.

Now, in U.P. the demand for nationalisation has come and there are reasons for that. The sugar industry is 30 to 35 years old. The earliest sugar industry was established in U.P. and Bihar. I know it because even at that time in 1937 I had to do something with the zonal system in U.P. and Bihar of the sugar industry. I have been associated with the sugar industry in U.P. and Bihar since 1937. Many factories were established before 1937. I am sorry to say that all these years very little has been done by the factory owners to rehabilitate or renovate those factories. I was looking into the figure; I have the figure with me, but I don't want to take up the time of the House. They are all available in the reports. Out of 71 factories in U.P. there are hardly 5 factories which are less than 10 years old. From that you can imagine what is the condition of the factories in U.P. Complaints were made about the arrears of the sugarcane prices due to the growers and about Govt. dues with these factories. It is not coming for the first time. Many times, I have told this House that I have been writing to the State Governments to take action for the recovery of the arrears of the sugar cane prices due to the growers and for recovery of arrears of their own, that it can be realised as arrears of land revenue. We can't take that action because the action has to be taken by the State Governments and we on our part have been reminding them to take action. It is for the State Governments to take appropriate action for realising these dues as arrears of land revenue.

The question of nationalisation has arisen in U.P. because of this fact of arrears and also because there are these old plants which are not having their proper, efficient functioning. The Member of Jan Sangh was waxing eloquent for the canegrowers. But the cat was out of the bag at the concluding sentence of his speech.

SHRI RANGA : What was it ?

SHRI JAGJIWAN RAM : It was that the efficient sugar mills should be nationalised, that they are doing very well. So all this sympathy for the cane growers—this is but normal for the Jan Sangh—is but a camouflage to protect—this is the real basis of the Jan Sangh—the vested interests in this country. I am not saying this myself. On going through the reports of the speech of the Jan Sangh member, you will find that in his opening sentence he shed crocodile tears for the cane-growers.

श्री शारदा नन्द : उपव्यक्ष महोदय मैंने स्वायत्त निगम की मांग की थी।

SHRI JAGJIWAN RAM : The demand was for a Sugar *Nigam*, not for nationalisation. That is why I am reiterating that. I do not want to drag the member of the Jan Sangh into a controversy, because I have not got that sort of culture that he has got. I will never aspire to that sort of culture. Let that culture be his monopoly.

As regards nationalisation, it was stated in the other House that according to the legal advice that we have got, if the UP Government thinks that in the context of the condition of the sugar industry in that State nationalisation is called for, there is no legal or constitutional difficulty in its proceeding with that (*Interruptions*).

AN HON MEMBER : What about the financial difficulty ?

SHRI M. N. REDDY What about Bihar then ?

AN HON. MEMBER: Is UP separate from the rest of the country ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Of course, U.P. is a part of the nation.

SHRI SHEO NARAIN : Why is he shifting away from his own responsibility ?

SHRI JAGJIWAN RAM : I am saying this because a persistent agitation for nationalisation is there in U.P. and a demand has come from there. It has not come from other States (*Interruptions*). I am coming to the other aspects also.

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) : The Sugar Mill Workers' Federation, of which Shri Kashinath Pandey is the President, passed a resolution recently to the effect that the sugar industry must be nationalised. We voted for it. He was presiding there. Now he betrays the interests of the workers. It is a ruse (*Interruptions*).

SHRI K. N. PANDEY : I say nationalise the entire sugar industry not just in U.P.

SHRI AMRIT NAHATA : It is in the constitution of their Federation also.

SHRI JAGJIWAN RAM : I know that many States are concerned with the sugar industry. Why I took special notice of U.P. was because the demand arose from there. Practically all the political parties including the one manning the Government wrote to me about nationalisation. Therefore, I have to take special notice of the conditions in U.P. Therefore, I said this.

So far as the industry as a whole is concerned, a study and investigation of the entire industry in depth is very necessary. Even if we have at one stage or the other to decide about nationalisation, certain information is very necessary. A study is necessary in order to get that information and see how the entire industry can be placed on a sound national footing so that it can sustain itself in helping the rural areas.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah) : The policy of the Congress Government is mixed economy. Is the Government going to depart from that or I does it still believe in mixed economy ?

SHRI JAGJIWAN RAM : To that my answer is very simple. The Industrial Policy Resolution is there.

SHRI RANGA : Therefore ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Therefore, that policy stands. Therefore, in mixed economy where is it said that if at one time the Government decides about nationalisation, the industry will not be nationalised ? I think the question is misplaced. Even at present so far as the sugar industry is concerned, we have got the sugar industry in the private sector, in the public sector and in the cooperative sector. We have got the sugar industry in all the three sectors.

SHRI S. M. KRISHNA : It is a mixed curse.

SHRI JAGJIWAN RAM : The sugar industry is over 30 years old now and many developments have taken place during

these years. It is, therefore, an opportune time to appoint a committee to study the working of the sugar industry in the context of the demand for nationalisation of sugar undertakings in certain areas. The scope of the enquiry would be left sufficiently wide to enable an enquiry being made into the causes underlying the present demand for nationalisation of the sugar industry and the manner in which the various problems relating thereto may be tackled. The committee may go into the factory-grower relationship, the payment of cane prices, returns to the factory, their working and performance, the conditions of the plant and machinery and other relevant matters. In dealing with sick mills, the Committee can suggest steps which will help improve the working of these mills. In dealing with the sugar industry in general and with the sick mills in particular, the committee should assess the financial, administrative and managerial problems involved as also the organisational structure necessary to implement the recommendations of the committee. I propose to set up this committee very quickly to go into the entire question of the sugar industry and make recommendations.

SHRI S. M. KRISHNA : What is the period within which they should report ? Kindly indicate.

SHRI JAGJIWAN RAM : We have not thought of the period, but it will be a reasonable period.

SHRI RANGA : Will that committee include some genuine representatives of cane growers also ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Yes, of course, that will be very important.

SHRI K. N. PANDEY : Also the workers.

SHRI JAGJIWAN RAM : Yes, workers also.

SHRI N. K. SOMANI : There is one important item that the Minister has not elucidated. The export quota will lapse unless we perform accordingly. So, we want to know what he thinks of it.

SHRI JAGJIWAN RAM : Of course, next year we expect that we will have the record production of sugar in this country. We will have to encourage consumption and we are also examining the possibility of exporting sugar.

17.39 HRS.

DISCUSSION *re.* FALL IN PRICES OF SUGAR AND GUR

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : About two years ago, the cane growers were having a very hard time. The Government came forward with partial de-control of sugar with the good intention that the cane growers must get some decent amount. I must congratulate the Government and the Minister for it, but in working it has not succeeded. The Minister clearly said that the cane growers must be given Rs. 100 per tonne minimum because 40 per cent of the sugar was allowed to be sold in the free market by the mills. In many cooperative mills Rs. 100 was given that year but only the private factories have not implemented it. When the cane growers represented to the Government, the Government said that they would compel them to pay, but have not paid so far. Only the private factory-owners made crores of rupees of profit. Then, last year, the Government, instead of compelling the factory people to pay Rs. 100, reduced the free market sugar quota from 40 per cent to 30 per cent, and when they did so, the factory people said that the Government have reduced it to 30 per cent and we are not able to pay anything except the minimum price. Then also we wrote to the Government that the factory people must be compelled to pay Rs. 100 as the minimum, but the Government kept quiet.

Now, this year again, the season has already started. Government always sleeps till the cane-crushing is over and in the end they come forward with an announcement of some policy only to benefit the factory people. I am very sorry that the agriculturists have got two enemies : one is the pests and parasites which affect the crop. The other is Government without a heart. I say that two years back